RAJYA SABHA

Friday, the 8th April, 1960/the 19th Chaitra, 1882 (Saka)

The House met at eleven of the clock, MR. CHAIRMAN in the Chair.

MEMBER SWORN

Prof. A. R. Wadia (Nominated).

PAPERS LAID ON THE TABLE

AUDIT REPORT (1960) OF THE DEFENCE SERVICES AND RELATED PAPERS

THE MINISTER OF REVENUE AND CIVIL EXPENDITURE (DR. B. GOPALA REDDI): Sir, I beg to lay on the Table, under clause (1) of article 151 of the Constitution a copy of the Audit Report, Defence Services, 1960 (including Report on the Appropriation Accounts of the Defence Services and the Commercial Appendix thereto for the year 1958-59). [Placed in Library. *See* No. LT-2073/60.]

STATEMENT ON THE INDO-PAKISTAN FINANCIAL TALKS HELD AT RAWALPINDI IN MARCH, 1960

DR. B. GOPALA REDDI: Sir, I also beg to lay on the Table a statement on the Indo-Pakistan Financial Talks held at Rawalpindi in March, 1960. [Placed in Library. *See* No. LT-2078/60.]

RESOLUTION *RE* NATIONAL LOTTERIES FOR RAISING FINANCE FOR SOCIAL SERVICE SCHEMES

SHRI DAYALDAS KURRE (Madhya Pradesh): Sir, I beg to move the following Resolution:

> "This House is of opinion that Government should organise National Lotteries to raise money for implementing the health and other social service schemes envisaged in the Plan."

इस रिजोल्यूशन के पीछे एक बड़ा मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त है । यह कहना चाहिये कि यह रिजोल्यूशन बाल मनोविज्ञान और प्रौढ मनोविज्ञान दोनों के ऊपर आधारित है । इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि बाल मनोविज्ञान में बच्चों के पीछे कौन सी प्रवृत्ति ऐसी है और उस प्रवृत्ति के आधार पर वह अपने जीवन में कौन कौन में काम करना चाहता है । उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वह किस चीज़ को देखता है और देखने के बाद उसमें कौन कौन सी अच्छाइयां हैं—इस बात की जान्कारी हासिल करना चाहता है । बच्चा उस चीज का अनुकरण करता है और उस चीज़ की जानकारी हासिल करके वह आगे अपने जीवन में अमल में लाता है और उसे सीखने का प्रयास करता है ।

दूसरी बात यह है कि उसमें किसी बात को जानने की बड़ी उत्सुकता होती है । वह देखता है कि उसके आसपास के वातावरण में कौन कौन सी ऐसी चीजे हैं जो कि उस के जानने लायक हैं और उनकी ओर वह अग्रसर होता है । हम देखते हैं कि मां-बाप अपने बच्चों को खिलौना देते हैं तो वह उससे खेलता है, कभी उसको तोड़ता है और कभी उसकी चीजों के बारे में जानने की कोशिश करता है । हम तो बच्चे को केवल खिलौना समझकर दे देते हैं ताकि वह उससे खेले; लेकिन वह यह जानना चाहता है कि इसमें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, किस तरह से यह खिलौना बना है और इस तरह से वह भविष्य में उस चीज़ को बनाने का प्रयास करता है । यह बाल-मनोविज्ञान का एक सिद्धान्त है । उसी के आधार पर हम प्रौढ़-मनोविज्ञान को देखते हैं । हम यह भी देखते हैं कि यह प्रवृत्ति जो उसके बचपन

[श्री दयाल दास कुर्रे]

में आ जाती है उसके जीवन का एक आधार बन जाती है और आगे चल कर प्रौढ़पन में भी वह आ जाती है। इस तरह से बच्चे के मन में नई चीजों को सीखने की धारणा बन जाती है। मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रवृत्ति होती तो वही है जो बच्चे के मन में बचपन में पैदा हो गई थी, लेकिन बड़े होने पर उसका रूप बदल जाता है। यूं कहिये गरीब आदमी यह सोचता है कि मैं धनी बनूं, कम पैसे वाला यह सोचता है कि मैं पैसे वाला बनूं। इसके साथ ही साथ उसके मन में यह भी रहता है कि मैं पैसे वाला बनूं तो कैसे बनूं? वह आदमी इस बात का प्रयास करता है कि मैं किस प्रकार से धनी बनूं। वह आदमी अपने मन में सोचता है कि क्या मैं हमेशा गरीब बना रहूंगा? इस चीज की जानकारी हासिल करने के लिये वह ज्योतिषी के पास जाता है। किसी ने उसे बता दिया कि तुम्हारे ललाट मे यह लिखा हुआ है, तुम्हारे हाथ की लकीरें यह बतलाती हैं, इसलिये ज्योतिषी को अपना हाथ दिखलाओ। इन सब बातों का उसके मन में असर होता है और वह इस चीज़ का भी प्रयास करता है। आज हम देखते हैं कि बहुत से पंडित बाजार में भाग्य की दुकानें खोल हुए हैं। जैसा कि मैंने बतलाया कि मनुष्य के मन में इस तरह की प्रवृत्ति काम करती है और वह बाजार में जा कर ज्योतिषी को अपनी हस्तरेखा दिखलाता है।

दूसरी धारणा मनुष्य के मन में यह रहती है कि अगर वह सब प्रकार से धनी है, बड़ा आदमी है लेकिन निस्सन्तान है। संतान प्राप्त करने के लिये उसके मन में यह प्रवृत्ति पैदा होती है कि वह ज्योतिषी के पास जाये और उसे अपनी हस्तरेखा दिखलाये। इसके साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि जब विद्यार्थियों की परीक्षा नजदीक आ जाती है तो उनमें एक तरह की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है कि हम इस वर्ष किस तरह से परीक्षा में पास होंगे। बहुत से विद्यार्थी जो बी० ए० और एम० ए० की परीक्षा देते हैं अपने मन में एक अंक किताब का बना लेते हैं और इस भावना से यह चीज़ करते हैं कि अगर वह अंक खोलने पर आ जायेगा तो वे आने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण हो जायेंगे। अगर किसी विद्यार्थी ने अपनी किताब का ९० अंक अपने मन में रखा है और वह उसको खोलते ही निकल आता है तो वह समझ जाता है कि मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त है जिसके पीछे आदमी की मनोवृत्ति काम करती है। यह एक व्यावहारिक चीज़ है और उसी के आधार पर आदमी चलता है।

जैसा कि हमारा प्रवृत्ति के साथ विशेष सम्बन्ध है और हम देखते हैं कि हमारे अधिकांश कार्य भारतीय सभ्यता में समाविष्ट हो गये हैं। हम कभी कभी अपने कार्य भाग्य के ऊपर भी छोड़ देते हैं। गीता में जैसा कहा गया है और जैसा कि बहुत मे विद्वान जानते हैं कि हमारा अधिकार केवल कर्म के ऊपर है, उसके फल के ऊपर नहीं है। इसमे दो सिद्धान्त हैं। हम काम करते रहें और फल की आशा न करके काम करते चले जायें।

दूसरी चीज यह भी है कि हम अपने भाग्य के ऊपर भी भरोसा करते हैं। मनुष्य काम करते करते थक जाता है लेकिन उसको वह चीज प्राप्त नहीं होती जिसके लिये वह कार्य करता है। इस तरह मे वह अन्त में इस चीज को अपने भाग्य के ऊपर छोड़ देता है। तो जैसा कि मैंने अभी बतलाया कि समाज में इस तरह की मनोवृत्ति काम कर रही है और उसमें ज्योतिषी और हस्तरेखा का भी एक स्थान है। इन सब चीजों के आधार पर मनुष्य अपना काम करता चला जा रहा

है। जो मनुष्य भाग्य की आजमाइश करता है और उसके ऊपर पैसा खर्च करता है तो हमें यह देखना चाहिये कि उस पैसे का फायदा समाज में कौन व्यक्ति किस रूप में उठा रहा है। हमारा यह कर्तव्य होना चाहिये कि किस तरह से उस पैसे का उपयोग समाज के भलाई के कार्यों में लगा सकते है। तो उसे हम किस तरह से अपने समाज में व्यवस्थित ढंग से रखें और उसका उपयोग करें और यह प्रवृत्ति जो मनुष्य में है उसका किस रूप में हम फायदा उठायें—इस विषय से मेरा विशेष सम्बन्ध है। आज इसका फायदा व्यक्ति विशेष उठाता है—जैसा कि मैंने विद्यार्थियों का उदाहरण दिया। और लोग, जो भाग्य की आजमाइश करते है, उसका फायदा ज्योतिषी उठाते है। इसके अतिरिक्त दैनिक पत्रों में भी हम पढते है कि बहुत से क्रॉसवर्ड्स आते हैं। खाली स्थान भरो—यह भी आता है, और उनके ऊपर कुछ इनाम की बातें रहती हैं कि अमुक बातें करेक्ट होंगी तो पांच हजार या दस हजार का इनाम मिलेगा। यह भी भाग्य की आजमाइश है। उसमें थोडी सी रकम कुछ शर्तों के साथ रख दी जाती है। एक पत्र में मैंने देखा था जिसमें केवल चार आने की शर्त रखी गई थी। विशेषकर जो साप्ताहिक पत्र आते हैं जैसे "धर्मयुग" उसमें मुझे देखने में आया कि बहुत बड़ी रकम इनाम के रूप में रखी जाती है, यह जो इतनी बड़ी रकम पारितोषिक के रूप में रखी जाती है हो सकता है कि उसमें उनको अधिक फायदा होता हो और अधिक फायदा होने पर भी वे कम रकम देते हों। इस प्रकार इससे व्यक्ति विशेष फायदा उठाता है या एक खास आदमी को फायदा होता है जो इस काम को करता है। इसी तरह से, जैसा कि मैंने बताया, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर लाटरी रखी जाती है, जिनके ऊपर इनाम रखे जाते हैं, ताकि उनका उपयोग इस तरह से समाज में हो कि समाज से एक बहुत बडी रकम निकल आये। तो हम यह देखते है कि इस तरह से अव्यवस्थित ढग से समाज में यह चीज हमारे सामने आई है। यदि इसे हम व्यवस्थित रूप में रखें और यह जो रकम हमारी इधर उधर बिखरती है और खास आदमियों के पास जो एक रकम चली जाती है, उसे यदि हम ठीक तरह से काम में लायें और उसका उपयोग देश के हित को सामने रख कर करे, तो यह हमारे हित में बहुत ही अच्छी चीज होगी।

आप देखिये कि स्वतंत्रता मिलने के बाद से हमने अपने देश को सुधारने का बीड़ा उठाया। इससे हमारी सरकार के सामने धन की एक बहुत बड़ी समस्या आई। ये जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है जिनमें हमारे देश के ८५ प्रतिशत लोग रहते हैं, उनकी तरक्की का भार विशेषकर के कम्युनिटी डेवलपमेंट मिनिस्ट्री पर आया। इस मिनिस्ट्री ने इस बड़े बोझ को उठाने का बीड़ा उठाया। इसके अन्तर्गत हम देखते हैं कि आज बड़े बड़े काम लिये जा रहे है। बड़े शहर से लेकर सुदूर गावों की ओर जाइये, तो गावों में आपको कई काम देखने को मिलेंगे। वहां पर हम देखते हैं कि स्कूल बन रहे है। वहां पर हम देखते हैं कि छोटे-से औषधालय बन रहे है। वहां पर हम देखते है कि छोटी सड़कें—ऐप्रोच रोड्स—बन रही है। वहा पर हम देखते है कि नवयुवकों का संगठन हो रहा है, महिलाओं का संगठन हो रहा है। वहां पर हम देखते हैं कि ग्रामीण उद्योग-धंधे चालू किये जा रहे है। वहां पर हम देखते हैं कि पानी पीने की सुविधा के लिये कुएं तैयार किये जा रहे है, जानवरों और मनुष्यों के दैनिक इस्तेमाल के लिये तालाब बनाये जा रहे हैं। ये सारे बड़े अच्छे अच्छे काम आज गावों में हो रहे हैं और उनका बोझ हमारे कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पर है। यह हम देखते हैं कि इसमें अधिकांश

[श्री दयाल दास कुर्रे]

पैसा सरकार का लगता है । ये जितने काम हैं, जिनका मैंने अभी नाम लिया जैसे स्कूल बनाना, ऐप्रोच रोड्स बनाना, इत्यादि, इनकी स्थापना के लिये जो कंडीशन है उसके अनुसार आधी रकम सरकार देती है और शेष आधी रकम की आशा हम उन गांव वालों से करते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और जिनको अपने पेट के ही लाले पड़े रहते है । इस कारण हम यह देखते हैं कि सरकार जो काम गांवों में करना चाहती है उनको वह वहां कर नहीं पा रही है क्योंकि जो कंडीशन्स हैं वही नहीं पूरी होती है । बी० डी० ओ० साहब वहा जाते हैं और हर तरह से प्रयत्न करते हैं, किन्तु कंडीशन्स पूरी नही होती है जिसकी वजह से काम आगे नही बढ़ता है । इस प्रकार पैसे के अभाव में अधिकाश काम अछूता रह जाता है । इसलिये मेरा यह निवेदन है कि सरकार ऐसा मार्ग अपनाये जिससे पब्लिक मनी हमारे पास आये और पब्लिक मनी इस रूप में हमारे पास आये कि देने वाले को कोई बोझ न पड़े । ऐसी एक चीज हमारे सामने आई है । पैसा इकट्ठा करने के लिये सरकार ने एक चीज निकाली है और वह है स्मॉल सेविंग्स सर्टिफिकेट । इससे जनता के पास जो जमा रकम है वह सरकार के पास आ रही है । कई लोग अपना धन जमीन में गाड़ देते हैं । जब उनको यह बात समझाई जाती है कि तुम्हारे पैसे का उपयोग देश के हित में होगा, साथ ही साथ तुमको कुछ रकम ब्याज के रूप में मिलेगी और जो यह होता है कि कभी कभी तुम्हारी रकम को चोर निकाल ले जाता है, कभी डाकू छीन ले जाते हैं, कभी कोई बात हो जाती है, उसका भी भय नही रहेगा, तो इन सब बातों को समझाने का उनके ऊपर बहुत कुछ प्रभाव पड़ रहा है । यद्यपि उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा है जितना कि हम चाहते हैं । यह एक रास्ता तो है लेकिन साथ ही साथ जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि मनुष्य में आज़माइश करने की एक बहुत बड़ी प्रवृत्ति होती है । इसलिये जितनी सुविधायें गावों में होने जा रही हैं, उनका ठीक तरह से अमलीकरण करने के लिये, उनका ठीक तरह से निर्माण करने के लिये हमें कोई ऐसा रास्ता अपनाना चाहिये जिससे जो पब्लिक मनी है, जो जनता के पास रकम है, वह उनसे निकल आये और उनको मालूम भी न हो । इसलिये उनके सामने एक आकर्षण का साधन रखना बहुत ही आवश्यक है । दैनिक पत्रों और साप्ताहिक पत्रो के सम्बन्ध में जैसा कि मैंने बताया, उसी प्रकार का हम कोई आकर्षण का साधन निकालें । इस सम्बन्ध में मैं आपसे निवदन करूं कि विकास खंडों में जो ग्राम सेवक काम करते हैं उनमें परस्पर स्पर्द्धा शक्ति लाने के लिये कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट अफसरों ने एक बड़ा अच्छा उपाय निकाला है । यह कह दिया जाता है कि जो ग्राम सेवक सबसे अच्छा काम करेगा उसको इनाम के रूप में एक साइकिल मिलेगी या सौ दो सौ की एक घड़ी मिलेगी अभी मुझे एक विकास खंड में जा कर के देखने का मौका मिला । मैं ने देखा कि वहां एक सुन्दर लाल नामक ग्राम सेवक को २५० रु० की एक अच्छी साइकिल मिल गई । वह बड़ा खुश था और आगे का उसका कार्य और भी अच्छा रहेगा । तो इस तरह से दूसरे विकास खंडों में जो ग्राम सेवक हैं, बी० डी० ओ० हैं—उनको भी अवसर है । यह चीज अभी हमारे अनजाने में हो रही है । मेरा अध्यक्ष महोदय, आपसे नम्र निवेदन है कि यदि हम इस चीज को देश के हित में सरकारी स्तर पर करें तो सम्भव है कि यह जो हमारी आर्थिक समस्या है, जिसका कि हमारे प्लान से, हमारी योजना से, विशेष सम्बन्ध है, वह बहुत कुछ हल हो जायेगी । इसके लिये केन्द्रीय स्तर पर, स्टेट के स्तर पर यदि हम यह रखें कि भाई एक मोटर या एक जीप एक ऐसे काम के लिये हम इनाम के तौर पर रखते

है और हर एक व्यक्ति को जोकि इसमें भाग लेना चाहते हैं उसको एक एक रुपया देना है तो काफी अच्छी रकम आ सकती है। मालूम नहीं कि किसको यह जीप चली जाये, यह मोटर चली जाये, यह कहा नहीं जा सकता है। इसके लिये एक सीमा निर्धारित कर दें और इसका एक ऐलान सरकार की तरफ से हो। सरकार की ओर से कोई भी काम किया जाता है तो मेरा यह विश्वास है कि सारी जनता का उस पर पूर्णतः विश्वास रहता है। वही काम यदि एक व्यक्ति करता है तो उसके ऊपर विश्वास कम रहता है कोई भी काम जो कि सरकार की ओर से किया जाता है उसकी एक साख रहती है। जैसे कि बैंक्स हमारे चल रहे हैं और इनके ऊपर लोगों का ज्यादा विश्वास है क्योंकि वे समझते हैं कि सरकार के द्वारा ही ये सब चलाये जा रहे हैं। जब लाइफ इंश्योरेंस कम्पनियों का नेशनेलाइजेशन नही हुआ था, कई लाइफ इंश्योरेंस कम्पनियां डूब गई, इसलिये लोगों का उनमें विश्वास नहीं था और वे पेमेंट नहीं करते थे। अब इसकी सक्सेस का कारण यह है कि इसको सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। तो आप देखिये कि कोई भी काम जब सरकारी स्तर पर होता है तब उस पर जनता का विश्वास अधिक होता है। इसी आधार पर मेरा यह निवेदन है कि यदि यह काम भी सरकार अपने हाथ में ले और यह पारितोषिक देने की जो चीज है उसको लाटरी के रूप में समाज में रखें तो यह ज्यादा सफल कार्यक्रम हो सकता है और इसका उपयोग जो सरकारी योजनायें हैं, जो योजनायें चल रही हैं उनमे हो सकता है। कही कहीं पर हम देखते हैं कि ये हमारी जो योजनायें हैं वे बहुत कुछ असफल हो रही हैं पैसे के अभाव में और हमें विदेशों से भी बहुत रकम लेनी पड़ रही है। वे आंकड़े हमारे सामने हैं। तो मैं देखता हूं कि इस तरह से यह जो आज पब्लिक के पास रकम जमा है उसका हम ठीक तरह से उपयोग कर सकेंगे। सरकार इसे यदि अपने हाथ में लेती है तो जनता का इस ओर अधिक आकर्षण होता है और उनकी पाकेट से—उनकी गाठ से—जो रकम इसमें आती है उसके बारे मे देने वालों को यह आभास भी नहीं होने पायेगा कि हमने कितनी रकम दी है। वे तो यही समझेंगे कि एक आजमाइश थी और इसको हमने आजमाया दूसरी बात उसके दिमाग मे यह भी आती है कि हमने एक रुपया ही तो दिया है, यदि जीते तो पाच या १० हजार की जीप या कार हमारे पास होगी नहीं तो सिर्फ एक ही रुपया गया। तो आप देखिये कि यदि २० हजार रुपया एक छोटी सी लाटरी निकाल कर के आप इकट्ठा कर लें और उसमें से पांच हजार रुपये की एक जीप खरीद कर के लाटरी जीतने वाले को दे दें तो फिर इसमें क्या नुकसान है। बचे हुए पैसे को आप उस क्षेत्र में उपयोग में लायें जहां कि इसकी विशेष आवश्यकता है। इसके लिये आगे मेरा श्रीमन् से एक नम्र निवेदन यह भी है कि डिस्ट्रिक्टवाइज—जिले के आधार पर—लोगों की एक सलाहकार समिति बनाई जाये और सलाहकार समिति में यह निश्चय किया जाये कि इस प्रकार से लाटरी में, इस फंड में, जो रकम आयेगी उसका उपयोग किन किन कामों में किया जायेगा, अर्थात् कितने स्कूल बनाये जायें, जनपद सभा की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की तरफ से कितने अस्पताल खोले जाये, कितनी ऐप्रोच रोड्स बनाई जायें, कितने महिला-मंडल बनाये जायें, कितने नवयुवक-मंडल बनाये जायें या कितनी रकम स्काउट संस्था को दी जाये, और किन किन चीजों में किस तरह पैसे का उपयोग हो। हम देखते हैं कि यदि हमने लाटरी सिस्टम को अपने समाज में सरकारी स्तर पर ला कर के रखा तो यह समाज के हित के लिये, देश के हित के लिये बहुत ही अच्छी चीज रहेगी।

श्री किशोरी राम (बिहार) : बहुत बड़ा जुआ है।

श्री दयाल दास कुर्रे : मेरे सामने बैठे हुए मित्र कह रहे हैं कि बहुत बड़ा जुआ है, तो मैं उनसे यह नम्र निवेदन करूंगा कि ऐसी

[श्री दयाल दास कुर्रे]

बात नहो है। ग्राप एक बार ग्राजमाइश कर के देखिये कि हमारे समाज का पैसा देश के हित मे ग्रच्छे काम मे लगेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं श्रीमन् से नम्र निवेदन करता हू कि मेरा जो रेजोल्यूशन है उसको ध्यान में रखते हुए इसको सरकार ग्रपनी स्वीकृति देने की कृपा करे ग्रौर यदि इसमे सरकार को समाज का हित सही रूप मे दिखाई देता है तो ग्रवश्य ही इस ग्रपनाये ग्रौर शीघ्र ही केन्द्रीय स्तर पर, प्रान्तीय स्तर पर ग्रौर जिले के स्तर पर एक विधान ला कर के इसको कार्यान्वित करने के लिये सरकार प्रयत्नशील रहे । बस, इतना कह कर मै ग्रपना स्थान लेता हूं ।

The question was proposed.

SHRI BIREN ROY (West Bengal): Mr. Chairman, Sir, I heartily commend this Resolution for the acceptance of all sections of this House. It is taken outside in some important quarters as if lotteries would only propagate more of the gambling instinct, but that is not so. Even if it is so, I think that this Resolution permitting National Lotteries will not be worse than what the Government has already accepted in allowing horse-racing to go on unrestricted in India. In various States there was opposition and motions were moved in State Legislatures, but with Government's support those motions were defeated and tactics were adopted by our previous rulers to admit some rich men as Indian stewards and sometimes also as judges in Turf Clubs with the result that gambling on horse-racing which ruins the middle class people in Calcutta, Bombay and in other places is going on much more than it used to be in the British days.

There were restrictions on the number of days of horse-racing in Calcutta; now even on Sundays and holidays—except of course the national holiday on the 15th August—there is horse-racing. Most of the holidays have now been taken up by horse-racing. Previously there were approximately fifty days in a year for racing; now it is more than a hundred days. If you are in Calcutta—I have never been to the races myself, never even in the race-course at all—you will see millions of people there on the race days. Whether Mr. Khrushchev is coming or Mr. Nehru is coming, there is no question of stopping this mad rush to the races; it goes on, and there will be millions of people losing their money—sometimes borrowed not only on official bids but in unofficial gambling dens. The States sometimes raised objections that if they were to stop horse-racing, they would lose the tax. We had proved in the West Bengal Legislative Assembly before that the tax that they would lose. could be realised by other means but that was not accepted.

In this particular case of National Lotteries, even if we make a beginning, we will get a huge sum. In Ireland by conducting the Irish Sweep-stake they have built big hospitals. A small country like Ireland has done that by organising the sweep-stakes and if we do that also in the right manner, it will be useful. I would not mention here about the executive matters or how it should be organised and controlled and so on, but I think the lotteries in India can be the biggest draw in the world. It was once so. The Calcutta Derby was the most popular in the whole world and prizes were given to the extent of nearly 14 to 15 lakhs of rupees in those days before it was closed down.

There is one point in regard to these National Lotteries. If we organise them even in countries outside India, we can attract enormous amount of foreign exchange and give a part of the collections to winners. After all, 15 per cent. only as expenses is allowed in any lottery. If we take away from the collections about 40 per cent as stake money and 15 per cent. as cost, that is 55 per cent. in all, we are having a net earning of 45 per cent.

So if we organise this, there will be available an enormous amount of foreign exchange just as we get from foreign tourists coming to this country, and foreign exchange will flow into this land.

Sir, objection has also been raised in describing the Prize Bonds issued by the Government—which has been copied from Great Britain as an instrument to encourage gambling. But it was argued that this was not gambling and that the buyer of the Prize Bond got back the money paid by him for it in full after a time, i.e. 5 years and that there was no loss to the buyer for it. That is a fallacious argument because a person investing Rs. 100 in a hundred-rupee Prize Bond loses the interest on it for a period of five years since he gets back only Rs. 100, and if on the other hand, he had invested that money in a savings account or had that money put to use in a paying concern he would have earned a return of at least 5 per cent. per annum on it, which in five years would come to Rs. 25. And he loses this return by purchasing these Prize Bonds. From such losses incurred by the people you are paying the prizes. So you cannot just say that if we organised a lottery on the basis of the Resolution under discussion, and a person bought a one-rupee lottery ticket, he stood to lose that money and it would rouse the gambling instinct in him. That is not so because there is the loss to him whether in a lottery or in a Prize Bond scheme; it may be more in one case than in the other. Now let me take the five-rupee Prize Bonds. The poor fellow who buys a five-rupee Prize Bond also loses some money because if he would have invested that money in a savings bank account, or put it to productive purposes in the villages, he could have easily earned one rupee or at least eight annas a year. So in purchasing the five-rupee Prize Bonds also—it is mostly the low-income people who would go in for them—the loss of one rupee or eight annas a year in the shape of a return on the amount invested is there over a period of five years. Since loss is there in either case, it should not be argued that a person buying a one-rupee lottery ticket only stood to lose it. After all nothing is compulsory and a person need not buy it.

Moreover, the State Governments, Sir, have already allowed lotteries to go on in their respective spheres. For instance there is the Red Cross lottery and in West Bengal there are the K. C. Charities lottery, and the Don Bosco lottery in Calcutta for the benefit of the Portuguese boys' school and many others. There are also other lottery tickets coming from outside the country and they are coming from Sikkim and are sold in Kalimpong. As I mentioned before, at one time the biggest lottery in India was the Calcutta Derby. Also there are the mushroom lottery tickets that are not allowed and yet are being sold unauthorisedly. Perhaps only in one case out of a hundred the guilty persons are arrested. On the other hand, if we have National lotteries, and the States are also authorised to have their own lotteries, the unauthorised sale of banned and mushroom lotteries will automatically stop; people will not go in for them when they have these National lotteries. By having them we could pool the funds from all over the place and then utilise the money for implementing National schemes to be decided on from time to time. That is what I think has been envisaged by the Resolution; therein the principle has been proposed. The details can be worked out later. And if national lotteries are organised bearing the seal of the Government of India, we can sell them also in foreign countries and earn foreign exchange. I do not see why the Resolution should not be accepted in principle. They could be properly organised and the lotteries successfully run through the State Authorities; the sale of tickets could be done through the agency of the Local authorities, through the post offices, through the banks and so on. And if the demand for the lottery tickets is so great that these agencies cannot cope with, we can have the automatic machines, just as it is being

[Shri Biren Roy.]

done in foreign countries, in Germany, for example, in both the Germanys, Democratic Germany and the other Germany, the Germany of free enterprise as they call it. In these two Germanys they are running the lotteries by vending tickets through automatics. The automatic machines punch the tickets and the counterparts of the tickets automatically go out in a roll and these go to the place meant for the draw. It does not require much human agency. Money is only collected by men and the ticket counterfoils go for the draw. The lottery there is held every two months. Here we can have it every six months to start with and then make it every three months. Of course there are some lotteries of a gambling type, for example, the Sweep stakes in Ireland and the Rangers in Calcutta and so on, and through such lotteries they still get enormous money. That is pure and simple gambling. First of all the man's ticket must be drawn in the lot and then it is attached practically to the tail of the horse i.e. the name of a Race Horse is drawn with it, and if the horse to which it is attached does not win the money is not fully won. Only a consolation prize comes. Here it is not so. Here there will be only one draw and if a person is lucky enough he will get the full Prize money. Like Prize Bonds, the lotteries can also be divided in groups Statewise or otherwise. Here there do not exist two kinds of things, one gambling and one lot. So it is a very simple thing which we can accept and which, if implemented, will bring in crores of rupees to our Government to promote measures for the welfare of the people, to promote health, to promote education and other social services. Not only that, it will also earn foreign exchange, as mentioned, and that is an important aspect of it. We have banned now-a-days the entry of Irish Sweep Stakes and we have banned also other sweep stakes for which payment in foreign currency has to be made. But yet it is going on and foreign currency is being smuggled out of the country for that purpose and millions of such tickets are sold in India and the results of winning tickets are even announced in the papers. No action is taken. When the Government knows that this illegal thing is going on and is tolerating it, why should not our Government initiate these National Lotteries and collect money for the Plan, I cannot understand. So I think all sections of the House will accept and commend this proposal to Government.

If this is accepted, later on a porper board may be formed and, if necessary, there may be constituted such boards in the various States to run these National Lotteries. To begin with there may be two, and later four in a year. At the same time we may ban this horse-racing business because there the people are simply gambling and are losing heavily and since there is an outlet for those gamblers in these National Lotteries they will perhaps invest more also in these

श्री नवाबसिंह चौहान (उत्तर प्रदेश) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी मेरी तरफ जरा बड़ी प्रेम भरी निगाह से देख रहे हैं। शायद वह यह आशा रखते हों कि मैं इस प्रस्ताव का विरोध करूं।

डा० राज बहादुर गौड़ (आन्ध्र प्रदेश) : वह तो कभी आशा हो ही नहीं सकती।

श्री नवाबसिंह चौहान : मंत्री जी की आंखें भी शायद लाटरी का खेल देख रही हैं। लाटरी में भी एक आशा हुआ करती है और आशा ही के सहारे आदमी चलता है, अपना पैसा लगाता है, और आशा ही एक ऐसी चीज है कि जिसके सहारे, चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, इंसान का जीवन चलता है। अगर आशा इंसान के अन्दर से निकल जाये तो उसका जीवन ही निरर्थक हो जाये। इसलिये हमारे मित्र कुरें साह बनें जो यह प्रस्ताव रखा है—जिसका एक माननीय

मित्र ने अभी समर्थन किया है---उसका हृदय से स्वागत करता हूं और इसकी आवश्यकता समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से एक लाटरी चलाई जाये और उसका नेशनल लाटरी नाम रख लीजिये या और कुछ रख लीजियेगा । लाटरियां चलाने की बात आप ही नही करते है बल्कि, जैसा एक मित्र ने बतलाया, ये लाटरियां तो हर एक गली, हर एक कोने, हर एक पग पर चल रही हैं । सरकारी कामो में, गैरसरकारी कामों में लाटरियों के बगैर काम नही चल सकता है और हम राज्य सभा के सदस्य तो बहुत निर्भर रहते हैं लाटरी के ऊपर । जब पहली दफा हम चुन कर आए तो हमारी लाटरी ड्रा की गई ।

SHRI M. D. TUMPALLIWAR (Bombay): Only once it must be done by lots.

श्री नवाबसिंह चौहान : वन्स ही हम चाहते हैं, जरा वन्स कर दीजियेगा फिर उसका सिलसिला चालू हो जाता है, फिर वन्स ही नही हर बार करना पड़ता है । कोई दो साल में आया, कोई चार साल में आया, कोई छ: साल में आया । यही नहीं, बहुत से ऐसे कानून बने हैं चाहे वे चुनाव सम्बन्धी हों, चाहे और चीजों के हों कि जब बराबर वोट आयेंगे तो लाट ड्रा कर लीजियेगा । इसके मानी क्या हैं ? हमने इलेक्शन लड़ा, खर्च किया, सब कुछ किया और जब बराबर वोट आ गये तो आपने लाटरी क्यों निकाल ली । उसके लिये और कोई चीज सोचते और चलाते । अगर आप भाग्य के ऊपर, चांस के ऊपर निर्भर नही करते है, स्किल के ऊपर निर्भर रहते है तो ठीक है स्किल का काम निकालिये, भाग्य का सहारा कैसे ले लिया ? तो इसलिये आप किसी नैतिक आधार के ऊपर इसका विरोध नही कर सकते हैं । अगर सरकार विरोध करती है तो मुझे एक बड़ा ताज्जुब होगा । गांव की मसल है : गुड़ खायें और गुलगुले से परहेज । गुड़ तो हम खाते है लेकिन गुड से जो गुल-गुला तैयार होता है उसको कहते है कि बुरी चीज है । ये लाटरी बॉड्स जो आपने चलाये है जिनको आपने प्राइज बांड्स के नाम का सुन्दर जामा पहना दिया है यह वही चीज है जिसको विदेशों में लाटरी ड्राअल्स लोन्स कहते है । दोनों में कोई फर्क नही है । इसलिये नैतिक आधार तो आपका कुछ रहा नही । हा, आप यह कह सकते हैं कि आर्थिक आधार पर यह खराब है । आप यह कह सकते है कि हम सूद के ऊपर लाटरी लेते है । आपकी मूल पूंजी ज्यों की त्यों रहती है । यह भी आपका आर्ग्युमेंट फैलेशस है, इसमे हेत्वाभास है, क्योंकि जो दस रुपये का कैपिटल दे कर बांड खरीदता है वह क्या है । वह भी तो सूद है जो उसके मेहनत की उसकी नौकरी की, उसके पसीने की कमाई है । उसको अपनी मेहनत करने का सूद मिला । इसलिये आपका यह कहना कि वह कैपिटल सूद नही है, गलत है । मान लीजिये आपकी लाटरी में वह अपना रुपया नही लगाता और दस रुपया जमा कर देता है, या किसी को किश्त में उठा देता है और दस रुपये का एक साल में बारह रुपये हो जाता है तो दो रुपया जो सूद हुआ--इंटरेस्ट हुआ--वह कैपिटल में जुड गया और कैपिटल बन गया । तो इसलिये सूद और कैपिटल---दोनों मे फर्क करना और कहना कि हम कैपिटल पर तो लाटरी नहीं करेंगे, सूद पर करेंगे --यह बात कुछ समझ में नही आती, कुछ तर्कसंगत भी नही मालूम पड़ती । साथ ही साथ यह कहना कि भाई इससे गरीबों को नुकसान होगा तो यदि गरीब की मुरव्वत का खयाल है तो फिर बांड ही क्यो बेच रहे है ; वह रुपया उन्ही पर रहने दीजियेगा । आप कह सकते है कि यह रुपया जो आता है सरकार के कोष में आता है, इससे अच्छे अच्छे काम चलते हैं तो ठीक है उस रुपये की लाटरी खरीद कर जो रुपया आ जायेगा उससे भी अच्छे काम चलाये जायें । यह रिजोल्यूशन यह कहता है कि किसी प्राइवेट फायदे के लिये, निर्जी स्वार्थ

[श्री नवाबसिंह चौहान]
के लिये यह लाटरी नहीं चलाई जानी चाहिये। यह अस्पताल के लिये, किसी स्कूल के लिये और अच्छे काम के लिये उपयोग में लाया जाये।

इस तरह से एक एक रुपये की छोटी छोटी रकम इकट्ठी होकर आ जायेगी, तो इससे फायदा ही होगा। इस चीज़ के पीछे एक परमार्थ का आधार है और अगर कोई आदमी या माननीय मंत्री जी इसका विरोध करते हैं तो मैं समझता हूं कि उनके लिये इस तरह की बात कहनी ठीक नहीं होगी। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर राष्ट्र की ओर से इस तरह की लाटरियां चला दी जायेंगी तो इस समय देश के अन्दर जो बहुत सी गलत कार्यवाहियां इस सम्बन्ध में हो रही हैं वे सब बंद हो जायेंगी। बहुत से लोग इसे जुआ कह सकते हैं लेकिन जो मैंने आपके सामने मिसाल दी वह भी जुआ में शामिल हो सकती है। इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। पिछली मर्तबा हमारे माननीय सदस्य श्री पणिक्कर ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर सदन में प्राइज़ बांड्स का समर्थन किया था और एक ऐतिहासिक मिसाल महाभारत की युधिष्ठिर के बारे में दी थी। उस वक्त हमारे माननीय मंत्री जी ने उसका विरोध नहीं किया था और न किसी प्रकार की असहमति प्रकट की थी। उसी तरह से आज यह प्रस्ताव सदन मे लाया गया है और मैं समझता हूं कि इसका भी उसी तरह से माननीय मंत्री जी समर्थन करेंगे।

एक **माननीय सदस्य** : उस जुए से तो महाभारत की लड़ाई हुई थी।

श्री **नवाब सिंह चौहान** : उस समय जो महाभारत हुआ था उसमें दुष्टों का नाश हुआ था। जुए के अंत होने का परिणाम दुष्टों का नाश होना है। इसी तरह से अगर हमारे देश मे लाटरिया चलाई जायेंगी तो उसका परिणाम यह होगा कि जो दुष्ट आदमी अपने फायदे की दृष्टि से इस तरह की कार्यवाही करते हैं वे सब नष्ट हो जायेंगे। आज हम देखते हैं कि देश में हर कस्बे में इस तरह का सट्टा चलता है जिसमे लाखों गरीब लोग तबाह हो रहे हैं। जो दुष्ट आदमी इस तरह की कार्यवाही करते हैं वे गरीब आदमियों से पैसा प्राप्त करके फ़ायदा उठाते हैं। आज गरीब आदमियों को एक रुपया, आठ आने की सट्टे की टिकटें बेच कर ये दुष्ट आदमी काफी रुपया प्राप्त कर रहे हैं। इन्होंने देश के हर कस्बे में एक तरह का रोजगार चालू कर रखा है और लाखो रुपये इस तरह से एक कस्बे से गरीब आदमियों का चला जाता है। इसी तरह से विदेशों से भी कई तरह की लाटरियां चलाई जा रही हैं और यहां के लोगों का लाखों रुपया उन लोगों के पास जा रहा है। अगर सरकार की तरफ से एक रुपया या आठ आने की लाटरी निकाली जाये तो गरीब आदमियों का भी फायदा हो सकता है और वे लोग अपने भाग्य का खेल भी खेल सकते हैं। अगर सरकार ने यह कार्य किया तो लोग अपना शौक पूरा कर सकेंगे और जो बुराई इस चीज़ से हमारे देश में फैली हुई है वह भी दूर हो जायेगी। मुझे मालूम नहीं कि माननीय मंत्री जी ने इस चीज़ के आंकड़े इकट्ठे किये हैं या नहीं कि इस तरह से कितना रुपया हमारा बाहर चला जा रहा है।

आज हम देखते है कि विदेशों में कई तरह की लाटरिया चली हैं और यहां के लोग उनको खरीदते हैं जिसका नतीजा यह हो रहा है कि हमारे देश का काफी रुपया विदेशों को चला जा रहा है। डर्बी की लाटरी के टिकट आज १६ या १७ रुपये में बिक रहे हैं इसके साथ ही साथ यह भी देखने मे आया है कि हमारे देश के बहुत से लोग विदेशों में

इस तरह की लाटरियां चला रहे है। यहां के बहुत से लोग साउथ ईस्ट एशिया, जावा और अफ्रीका मे, जहां कि लोग अंग्रेजी का ज्ञान रखते है, इस तरह की लाटरियां चलाते हैं। इस तरह का रोजगार दिल्ली और अलीगढ़ इत्यादि जिलों से हो रहा है। इन देशों मे बड़े बड़े पोस्टर अखबारों में छपवाये जाते है। हमारे माननीय मंत्री जी कहते है कि हम एक्सेचेंज नहीं देंगे, वे किस तरह से वहां पर एडवर्टाइजमेंट करायेंगे। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो लोग इस तरह का कार्य करते है वे सब तरह की तरकीबें जानते हैं। वे लोग एक तरह का अंकों का खेल खेलते हैं और इस तरह से लाटरी चलाते हैं। यह लोग वहां से ब्लैंक ब्रिटिश पोस्टल आर्डर भेजने के लिये कहते हैं। जब इस तरह की लाटरियों का विज्ञापन अखबारों में निकलता है तो यह लिखा रहता है कि फीस में ब्लैंक ब्रिटिश पोस्टल आर्डर आने चाहियें, नाम से नही आने चाहिये। ब्रिटिश पोस्टल आर्डर दुनिया भर में एन-कैशबिल होते है। इस तरह से हजारों की तादाद में वहां से ब्लैंक ब्रिटिश पोस्टल आर्डर चले जाते हैं। जो अखबार इन लाटरियों को छापते हैं उन्हें एडवर्टाइजमेंट छापने के लिये ब्रिटिश पोस्टल आर्डर भेज दिये जाते है। इस तरह से ये लोग एक्सचेंज के झगड़े से भी बच जाते हैं। आज हमारे देश में जो घड़ियां इत्यादि चीजें स्मगल हो कर आ रही हैं वे भी इन ब्रिटिश पोस्टल आर्डरों की वजह मे ही आ रही है। इन ब्रिटिश पोस्टल आर्डरों को घड़ी खरीदने के काम में लाया जा रहा है और डाक के जरिये ये पोस्टल आर्डर हमारे देश के बाहर भेजे जा रहे है। यही नही हमारे डाकखानों मे हजारो रुपये के ब्रिटिश पोस्टल आर्डर इस सम्बन्ध में आते रहे है। एक एक दिन में सात सात और आठ आठ हजार के ब्रिटिश पोस्टल आर्डर आते हैं। हमारे सी० आई० डी० विभाग ने इस तरह की चीज को पकड़ा है। इस तरह से लाखों रुपया हमारे देश से बाहर जा रहा है। अगर सरकार की ओर से कोई कानूनी चीज हो जायेगी तो इस समय जो गैरकानूनी चीज हो रही है वह सब बन्द हो जायेगी।

मै तो यह समझता हूं कि नैतिक और आर्थिक आधार के अलावा इस समय देश की जो स्थिति है उसको देखते हुये यह जरूरी है कि सरकार को इस तरह का कोई कानून बनाना चाहिये जिससे हमारे देश का रुपया बाहर भी न जाये और लोगों को भी लाभ हो। इंडियन पीनल कोड में इस चीज को रोकने के लिये जो धारा है वह भी अच्छी तरह से इस चीज को नहीं रोक सकती है। जब तक वास्तविकताओं के आधार पर स्थिति को नहीं सुधारा जाता तब तक इसको नहीं रोका जा सकता है।

मेरा आप से यह कहना है कि आप इस सम्बन्ध में एक कानून बनायें और देखें कि यह चीज सफल होती है या नहीं। इसके साथ ही साथ सरकार को यह भी देखना चाहिये कि विदेशों में यह सिस्टम किस रूप में कायम है। यू० के० में तो लाटरी कानून द्वारा बंद कर दी गई है लेकिन इस समय भी वहां पर दो तीन किस्म की लाटरियां कानून के अनुसार चल रही हैं। इसके अलावा अमेरिका इत्यादि देशों में भी यह चीज किसी न किसी रूप में जारी है। आयरलैंड में भी लाटरी का चलन जारी है। यू० एस० एस० आर० में भी पिछली दो लड़ाइयों के बाद वार बौड्स के रूप में लाटरी सिस्टम चलाया गया है। वहां पर फ्री लाटरी टिकट दे दिये जाते थे और जब लाटरी ड्रा होती थी तो एक लाख रूबल तक का इनाम दिया जाता था। इस तरह मे लड़ाई मे जो खर्चा हुआ उसको वहां की सरकार ने वार बौड्स के रूप में धन एकत्रित करके पूरा किया। इसी तरह से लुसियाना, अमेरिका मे सब से बड़ी लाटरी का चलन है। वहां पर १८६८ से लाटरी

[श्री नवाबसिंह चौहान]

के चलन के लिये लायसेंस दिया गया। उन्हें उम्मीद थी कि इस तरह से करीब ४० हजार डालर प्राप्त हो जायेगा, मगर लोगों में इतना जोश था कि इस लाटरी के द्वारा २० लाख डालर प्राप्त हो गया।

इसी तरह से आयरलैंड में भी १९५४ में आयरिश हॉस्पिटल ट्रस्ट की तरफ से लाटरी का इंतजाम किया गया और उससे ९० लाख की आमदनी हुई। मैंने यह फिगर्स इसलिये दिये हैं कि हमारे माननीय मंत्री जी फिगर्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं। आस्ट्रेलिया में भी सिवाय साउथ आस्ट्रेलिया के बाकी पांचों स्टेट्स में गवर्नमेंट कंट्रोल्ड लाटरिया चलाई जाती है। इस तरह से वहां पर लाटरी के टिकट बेचे जाते हैं और एक साल में करीब दो करोड़ पौंड की आमदनी होती है। जब एक छोटे से मुल्क में जहां की आबादी बहुत कम है इतनी आमदनी हो जाती है तो हमारे देश की तो आबादी बहुत ज्यादा है और वहां से ज्यादा आमदनी हो सकती है। इसी तरह से न्यूजीलैंड में भी लाटरी के टिकट बेचे जाते हैं, जो आस्ट्रेलिया से आते हैं। आस्ट्रेलियन सरकार न्यूज़ीलैंड सरकार को ६ पैसे प्रति टिकट कर देती है। साथ ही साथ यह है कि जिन जगहों पर मैं गया वहां मैंने इस चीज़ को देखा। बर्मा में मैंने देखा कि पगोडाज़ के अन्दर राज्य की तरफ से खुले तरीके पर लाटरियां बिकती है। यूरोप के देशों में जो लोग गये है उन्होंने वहां देखा होगा कि हर जगह इस तरह का इंतज़ाम है। बहुत सी जगह सरकार की तरफ से यह व्यवस्था है कि इस तरह की लाटरियां बेची जाये ताकि कुछ आमदनी हो और देश में जो अच्छे अच्छे काम करने हों उनको किया जाये। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी निःसंकोच हो कर इस प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। उससे कोई नुकसान नहीं होगा। अगर वे इसमें कुछ फायदा नही समझते है तो इसमें कुछ नुकसान तो हो ही नहीं सकता है, बल्कि यह उसी पालिसी के मुताबिक है जिसका श्री गणेश उन्होंने प्राइज़ बॉन्ड्स निकाल करके किया है और यह ज़रा उससे कुछ और आगे बढ गया है। इसको जुआ समझना एक ग़लत चीज़ है। यह जुआ नहीं है। जैसा कि भाई कुरें जी ने बताया, भाग्य की आज़माइश सभी करते है। पढ़ने वाले लड़के जब इम्तिहान के लिये जाते हैं तो वे इस तरीके से किताब को निकाल करके देखते हैं। इस लिये मुझे आशा है कि निःसंकोच इस रेजोल्यूशन को पास किया जायेगा और मैं इसका हृदय से समर्थन करता हूं।

श्री बी० एन० भार्गव (उत्तर प्रदेश) : माननीय सभापति महोदय, आज जब मैंने अजेंडा देखा और यह देखा कि इस प्रस्ताव का नोटिस अनेक माननीय सदस्यों ने दिया है तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा कि देश में नदियों की बाढ से तो लोग पीडित होते ही है, क्यों आगे जा करके लाटरियों की बाढ़ मे देश बहने वाला है ?

यह मै मानता हूं कि हमारे देश को इस समय धन की बहुत आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि हमारी गवर्नमेंट को अनेकों योजनायें चलाने के लिये बहुत धन की आवश्यकता है, परन्तु हमको सोचना यह है कि हम देश के हित की दृष्टि से जिस काम को करना चाहते है, उससे देश का हित होगा या अहित होगा। यह हमको बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। अगर यह प्रस्ताव स्वीकृत होता है तो सोचना यह है कि इससे देश में किस प्रकार का वातावरण फैलेगा। वह वातावरण अच्छा होगा या दूषित होगा। हमारी जनता इस प्रस्ताव को किस दृष्टि से देखेगी और इससे हमारी गवर्नमेंट के प्रति जनता की क्या भावना होगी ?

यह मैं मानता हूं कि अनेकों प्रकार के ऐसे काम होते हैं जिनमें रुपया अधिक खर्च न करके, अधिक परिश्रम न करके, रुपया

कमाया जाता है। परन्तु प्रश्न तो यह है कि जो सिद्धांत हमारे भारतवर्ष को ४० वर्षों से सिखाया गया—विशेषकर महात्मा गांधी के द्वारा—कि हमारे साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहियें, उसको क्या अब भुला दिया जाये ? अगर हमारा यह साध्य है कि हम देश की उन्नति करें तो हमारे साधन भी अच्छे ही होने चाहियें। हमने अपने देश में सत्याग्रह किया, असहयोग किया, परन्तु हम पतन की ओर कभी नहीं गये। सदा हमारा मस्तक ऊंचा रहा। कभी हमने कोई बात छिप करके नहीं की। हमको देखना यह है कि आज जो भ्रष्टाचार देश में फैल रहा है उसका मूल कारण क्या है। उसका मूल कारण है केवल रुपये का मोह। अगर देश में रिश्वतें चलती हैं, अगर देश में चोरी डकैतियां होती हैं, तो यह केवल रुपये का मोह है। अगर हम अपनी सरकार से यह कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर वह लाटरी को चलावे, तो दूसरी ओर से क्या हम सरकार से यह नही कह सकते हैं कि रिश्वत के सम्बन्ध में एक योजना बनाई जाये। कानून के द्वारा रिश्वत लेना लिगेलाइज किया जाये और उसमें यह शर्त लगा दी जाये कि जो भी रिश्वत ली जायेगी उसमें से ५० या ७५ प्रतिशत देश के लिये देना होगा। इससे भी बहुत सा रुपया आसानी से मिल जायेगा। मुझे इस समय एक . . .

श्री किशोरी राम : एक चीज मै जानना चहाता हूं। देश में शराब का ठेका गवर्नमेंट देती है, उससे क्या देश का हित होता है ? उससे क्या देश का कल्याण होता है ? क्या उसको जुआ नही कहा जा सकता है ?

श्री बी० एन० भार्गव : कहने को तो हमारा जीवन ही जुआ है। कौन जानता है कि जो इस समय भाषण दे रहे हैं या जो प्रस्ताव पेश कर रहे हैं, वे कितने क्षण जीवित रहेंगे। जुआ तो जीवन भी है। परन्तु हम आज तक जिस आधार पर चले हैं, जिस आधार पर हमने स्वतंत्रता प्राप्त की है, उसको हमें भूल नहीं जाना चाहिये। यह उचित नहीं है कि जिन महात्मा गांधी की हम रोज दुहाई देते हैं। जिनके नाम का हमारे नेता रोज अपने भाषणों में स्मरण करते हैं, उनके सिद्धांत को हम इतनी आसानी से भूल जायें। यदि हमारा साध्य पवित्र है तो हमारे साधन भी पवित्र होने चाहियें।

मैं यह बतला रहा था कि मुझे इस समय एक दोस्त की याद आ रही है। हमारे जिले में एक पेशकार थे। वे साधु संतों की बड़ी सेवा करते थे, खूब ब्राह्मण भोज करवाते थे, परन्तु रिश्वत भी खूब लेते थे। एक बार एक बाबा स्वामी रामदास, जो दक्षिण की ओर रहते थे, झांसी आये। पेशकार साहब उनके विशेष भक्त थे। मैंने उनके सम्मुख कहा कि यह कहते हैं कि मै रिश्वत केवल इसलिये लेता हूं कि उससे मैं साधु संतों को खिला सकूं और मैं रिश्वत का एक पैसा भी अपने खर्च में नही लाता। इस पर वे स्वामी जी बहुत बिगड़े और कहने लगे कि तुम घोर पाप करते हो; दुगुना पाप करते हो। एक तो रिश्वत लेना ही पाप है और दूसरे उस रुपये को अच्छे काम में लगाना और भी बड़ा पाप है। इसी प्रकार मैं जानता हूं कि बहुत से डाकू लोग देवी जी के बड़े भक्त होते हैं। जब डाका डाल कर वे आते हैं तो ब्राह्मण डाका भोज करते हैं, प्रसाद बांटते हैं, देवी की प्रार्थना करते हैं कि हमको आगे भी ऐसा ही लाभ हो। यह उदाहरण मैं इसलिये नही दे रहा हूं कि मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रस्ताव की भावना या मनोवृत्ति बुरी है। मैं यह कहता हूं कि हम जो भी काम अपने हाथ में लें उसके सम्बन्ध में आगे दृष्टि रख करके देखें कि उसका प्रभाव क्या होगा। जब से पिछली लड़ाई खत्म हुई है तब से देश का वातावरण विशेष कर के रुपये के लिये हो गया है। लोग प्राफिटियरिंग करके या अन्य बुरे उपायों द्वारा रुपया कमाने का प्रयत्न करते रहते हैं। ऐसे लोग समय समय पर अनेक संस्थाओं को दान भी देते हैं, पुण्य भी करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने जो साधन

[श्री बी० एन० भार्गव]

अपनाया है वह पवित्र है, क्योंकि उनका जो साध्य मंदिर और धर्मशाला बनवाने का है वह अच्छा है। हमको गांधी जी ने यही समझाया था कि हमारा साधन, हमारा मार्ग भी पवित्र हो और ऐसा न हो कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिये हम किसी भी मार्ग पर चले जायें। यह बिलकुल हमारे सिद्धान्त, हमारी संस्कृति और हमारे धर्म के विरुद्ध होगा।

प्रस्तावक महोदय ने उदाहरण दिया कि यह वैसा ही है जैसा कि लड़कों को इनाम मिलता है या विकास खंड के ग्राम सेवकों को इनाम दिया जाता है। इसमें और इस प्रकार की लाटरी के सिद्धान्तों में आकाश पाताल का अन्तर है। एक लड़का परिश्रम करता है, अव्वल नम्बर लाता है, तब उसको इनाम मिलता है, वज़ीफा मिलता है। इसी तरह जब एक पुलिस वाला अपनी जान खतरे में डाल करके किसी की जान बचाता है या कोई नदी में बहा जा रहा हो, उसको बचाता है, तब उसको इनाम मिलता है। तो ऐसे इनाम देने के पीछे जो मनोवृत्ति है और लाटरी के पीछे जो मनोवृत्ति है, वे दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध हैं।

ऐसी दशा में हमको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब हम समाज सुधार करने जा रहे हैं, तो हमारे उपाय भी धर्ममय हों, पवित्र हों। परिश्रम करके हमको रुपया इकट्ठा करना चाहिये, बजाय इसके कि हम सरकार से यह कहें कि वह लाटरी की कोई योजना बनाये। हम इस बात पर क्यों न ज़ोर दें कि हमारे देश में जो धनी मानी लोग हैं उनकी मनोवृत्ति को बदलने के लिये एक योजना बनाई जाये जिससे वह लोग स्वत: और स्वतंत्रतापूर्वक हमारी योजनाओं के लिये रुपया दे। इस प्रकार हमको ऐसा वातावरण उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होगी कि हम लाटरी के साधन की शरण लें।

12 NOON

SHRI MOHANLAL SAKSENA (Nominated): Mr. Chairman, I have listened to the speeches delivered in support of the Resolution and I am sorry I cannot see my way to support it for several reasons. First of all, it is not in keeping with our policy and professions. Secondly, it cannot have and should not have any place in a State which stands for planned economy and thirdly it is not in consonance with the object of socialism which we have placed before ourselves. I know that arguments have been advanced in favour of the Resolution because of the Prize Bonds recently introduced by the Government. I will have to say a few words about them, but before I deal with the Prize Bonds themselves, I would like to point out the harm that is likely to be caused to the people at large by the introduction of the system of National Lotteries. It has been said that nobody will suffer any harm if a man spends a rupee today and again a rupee tomorrow in buying lottery tickets because by doing it he does not lose anything as he spends the money that he has saved or whatever little he has got hoping that in the long run he might win a fortune. I think this itself causes a great deal of harm to the man himself. We have been told that man is the maker of his own fortune. Even those people who believe in the theory or *karma* know that they have got to work hard. We may leave the results in the hands of God but we have got to work and we have to strive hard. This system of National Lotteries will spread not only in the district towns but to every tehsil and every village. This is already going on and, therefore, we have to find some way—a legalised way—for canalising these activities. I think the greatest harm that the system will be doing is to create a feeling amongst the people that they should not depend upon themselves for changing their fortunes. The previous speaker mentioned the fact that Gandhiji used

to tell us that we have to attach special importance to the means, that it is the means that have to be taken care of and that the ends will be taken care of automatically. That is why he said that he would not have *swaraj* at the cost of truth and non-violence. I might refer to an incident in 1940 when negotiations were going on between Gandhiji and the then Viceroy, Lord Linlithgow. Agreement had practically been arrived at and Congressmen were advised to join the national Government that was to be formed. At the last moment, Gandhiji felt that the Viceroy was under the impression that the Congressmen would actively support Government's war effort. His colleagues told him, "You have not given any assurance to that effect. So, why bother about it?" But he said, "No. The Viceroy is under that impression," and so before he left Delhi, he informed the Viceroy that if the Congressmen joined the Government, they would not give active support to the Government's war effort. The result was that the negotiations fell through. This was against the advice of his colleagues who had said that he was not bound to tell him but he did not listen. There are men who would say that if he had not done that, perhaps the country would have saved a lot of travail and suffering but we know that if he had accepted that view, the country might have been in a worse position and he would not have had the feeling of having achieved the goal by our own efforts, but would have felt that somebody had given something by way of gift. So I feel that this would create a feeling in the minds of the people that instead of self-reliance which we want everybody to practise, instead of mutual co-operation and mutual help to propagate which we want to start co-operative societies, we shall switch their minds in a totally different direction. Secondly, as has been pointed out, in recent years there has been a great fall in our morals, especially because of the get-rich-quick mentality. Many of our present ills may be ascribed to that and once we introduce this system, I think we will be adding fresh incentive to that spirit. Instead of working for themselves, instead of devising ways and means to establish themselves, they will be thinking and depending on their luck, that is, they will be thinking that they will get a lottery prize sooner or later after which they will make a start in life. In a socialist State we do not envisage rich and poor persons. If a person gets Rs. 25000 by means of a lottery then he becomes a rich man in a village. This will create a new class of people—those who win and those who do not win. I think this is objectionable. There are two objections to these Prize Bonds. First of all, the prize money should not be given in cash. Secondly, I would not like these Prize Bonds to be bearer Bonds.

Some time back I had suggested the issue of bearer bonds but for a different purpose. In 1949 I had suggested that bearer bonds might be issued at a premium of 35 per cent. to attract black market money. There was plenty of it in the country then and it was causing a lot of harm to society, undermining the very foundation. This money was being utilised for anti-social activities. We had at that time appointed the Income-tax Investigation Commission and it was pointed out that if we were to issue some kind of bearer bonds like I had suggested, it would have meant that we did not want to stick to our original idea of appointing the Commission which was to ferret out black market money. Later on, it was found that with all its efforts the Commission could not ferret out more than Rs. 45 crores for which sum settlements were made with the parties concerned. At the time of the appointment of the Commission it was estimated that the money underground was to the tune of about Rs. 400 to Rs. 500 crores, and even now a considerable part of this amount was underground and was causing great

[Shri Mohan Lal Saksena.]
havoc. During the Second Plan period, the Investigation Commission had ceased to function and, therefore, I had suggested the issue of bearer bonds at a premium to attract the black market money and those who knew something about it assured me that it would be possible to draw at least Rs. 150 to Rs. 200 crores. Now the Prize Bonds that have been issued are bearer bonds and any person can invest his black market money in these Bonds. I am sure that the black market money has found its way into these bearer bonds because the purchasers have not to go in for *benami* transactions or even to buy bonds in the name of sons or relations. These are bearer bonds and anybody can buy them. I now understand that owing to the supply having been exhausted, there is already a black market in these Prize Bonds. A Five-rupee Bond is selling for a higher price. If Government had issued bearer bonds at a premium to attract the black market money, then the black market money would have been attracted and the Government also would have gained by way of premium. Firstly, I would like the Finance Minister to provide sufficient safeguards to see that the black market money is not invested in these Prize Bonds.

Secondly, he should issue bearer bonds at a premium of, say, 25 or 30 per cent or at any rate that his advisers advise him. For attracting the black market money it is necessary. And as regards prize bonds my suggestion is this that instead of cash prizes it would be much better if the prizes are given in the form of social services. For instance, you can issue housing bonds for the sake of solving the housing problem. In a particular city you develop the land and you issue bonds and instead of giving them interest you can have a number of houses built and you can draw lots because you do not have sufficient number of houses to go round for everyone. Those persons who have taken bonds instead of taking interest can naturally get houses and I think that way we would be solving the housing problem to a certain extent.

SHRI ABHIMANYU RATH (Orissa): That means the person has to migrate to the place where the houses are built?

SHRI MOHAN LAL SAKSENA: You can have a scheme for each particular city and the persons who live in that city will participate in that scheme.

SHRI ABHIMANYU RATH: In every city the Government should construct houses?

SHRI MOHAN LAL SAKSENA: It need not be houses throughout. You can develop orchards. What I mean to say is, if you want to give prizes, you must give something which meets one of their social needs. For instance, there are large areas of land along the railway lines. They have got to be developed. You have got so much of waste land. I understand in foreign countries they do cultivation right up to the railway track. But things are different here. Why can't we develop these lakhs and lakhs of acres of land which are lying fallow? The Government of India and the Railway Ministry can take this up. We can develop these lands into orchards and we can issue orchard bonds. And there are retired persons who would like to take up some such work. And because we do not have a sufficient number of orchards to go round, we can have a lottery. That will not have an element of gambling; but there will be the element of mutual help and self-reliance. I think some 50 persons can join together and can have 50 houses in five years or ten years. As to who should get the first house, that can be decided by drawing lots. Mr. Nawab Singh pointed out that there was the system of lottery everywhere. Lottry itself is not a bad thing but it does not mean you must support

every form of lottery; I cannot accept that argument. Mr. Chairman, my submission is, having issued these prize bonds sufficient safeguards have to be provided against black market money finding its way into these and being invested in bonds. Secondly, we should issue bearer bonds at a premium to attract black market money and that will help our finances. In any case, I do not see my way to support the Resolution.

श्री जयनारायण व्यास (राजस्थान) : सभापति जी, जिन प्रस्तावकों ने यह प्रस्ताव रखा है वे धन्यवाद के पात्र हैं, इसलिये नहीं कि प्रस्ताव अच्छा है बल्कि इसलिये कि उन्होंने यह प्रस्ताव रख कर लाटरी के बारे में हम कुछ कह सकें इस तरह का हमको मौका दिया ।

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

इस लाटरी को चालू करने के पक्ष में मुझे दो, तीन भाषणों को सुनने का अवसर मिला और थोड़ा आश्चर्य हुआ और बहुत दुःख भी हुआ विशेषकर श्री चौहान के भाषण को सुनकर । उन्होंने बड़ा परिश्रम किया—जैसा वे प्रश्न बनाने में परिश्रम करते हैं । देश विदेशों की बहुत सारी बातें उन्होंने एकत्रित की हैं । मैं कम बोलने वाला हूं और मैं समझता हूं मुझे सही बात बोलनी चाहिये और यह लाटरी के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव रखा गया है उसका घोर विरोध मुझे करना चाहिये ।

कोई भी चीज़, अच्छी या बुरी, उस भावना से बनती है जिस भावना से हम काम करते हैं । भावनाओं के अनुसार अच्छे या बुरे परिणाम निकलते हैं । अच्छी भावनाओं से अच्छे और बुरी भावनाओं से बुरे काम बनते हैं ।

श्री किशोरी राम : लेकिन यह प्रस्ताव तो अच्छी भावना से लाया गया है ।

श्री जयनारायण व्यास : इस प्रस्ताव की भावना अच्छी है । लेकिन प्रस्ताव को रखने वाले यह नहीं समझ सके कि इस प्रस्ताव के अन्दर कितनी खराबी है और अगर यह प्रस्ताव पास हो जायेगा तो किस तरह की भावना समाज में फैलेगी । इसको वे समझ नहीं पाये हैं इसलिये मुझे उनके अज्ञान के लिये सहानुभूति है । इसको मैं नहीं कहता हूं कि प्रस्ताव में कोई अच्छी भावना नहीं है । मैं आप से अर्ज़ करूं कि कोई चालीस वर्ष पहले मुझे सार्वजनिक जीवन में आने का मौका मिला और इस सिलसिले में रुपया पैसा भी हमने लोगों से लिया । हमको बहुत पैदल जाना पड़ता था, तकलीफ उठानी पड़ती थी, गालियां मिलती थीं, लेकिन कभी कभी लुक छिप कर कोई पांच रुपया दे भी देता था । एक भड़भूजे ने चुपचाप आकर पचास रुपये भी मुझे दिये और मैं जानता हूं वे पचास रुपये जो थे उसने हमारे अन्दर जो जागृति पैदा की और जो जान फूंकी । आज करोड़पतियों से जो पैसा हमारे पास आता है वह उतनी ही फूट और उतनी ही बेईमानी हमारे अन्दर फूंक रहा है । तो पैसे का जो बल है वह काम नहीं करता है बल्कि जिस भावना से पैसा दिया जाता है या पैसा लिया जाता है उसका असर होता है । फिर भी जिस वक्त ये प्राइज़ बांड निकले थे मेरे दिमाग में आया कि सौ रुपये के बांड खरीद लूं तो क्या बुराई की बात है । लेकिन फिर बाद में सोचा कि बांड खरीदना चाहिये या नहीं खरीदना चाहिये । अभी तक मैंने बीमा भी नहीं कराया क्योंकि मैं बीमे को बहुत अच्छा नहीं समझता । लेकिन इस बात को मैं समझता हूं कि अगर लाटरी में मुझे दस हजार रुपये पांच रुपये देने के बाद मिल सकते हैं तो मेरे दिमाग में यह बात होगी कि न तो मुझे कारखाने में जाना है, न मुझे कोई अध्ययन करना है, न मुझे कुछ लिखना पढ़ना है बल्कि मुझे तो कोई न कोई लाटरी लेनी है । एक मेरे मित्र थे जो बड़े अच्छे कांग्रेसमैन थे । वे चार-चार आने की लाटरी लगाया करते थे । हर महीने लाटरी आया करती थी । पहली तारीख को, पन्द्रह तारीख को, अठ्ठारह तारीख को लाटरी लगा करती थी और सबमें वे बराबर

[श्री जयनारायण व्यास]

पैसा खर्च करते थे। मैं उनसे कहा करता था--फिर बाद में वे कम्युनिस्ट हो गए--कि भाई पैसा क्यों लगाते हो ? वे कहते, "साहब पैसा तो हम कमा नहीं सकते, हमारा दिमाग काम नहीं करता है। इसलिए यह पहली तारीख की लाटरी है जो कि तीन महीने के बाद पहली तारीख को निकलेगी उस में इनाम नहीं आयेगा तो पन्द्रह तारीख की लाटरी में देखेंगे और उसमें नहीं आया तो बीस तारीख को देखेंगे।" हमेशा इस आशा ही आशा में वे गुजर चला लेते हैं। तो यह आशा बनना हमेशा रचनात्मक प्रवृत्ति की नाशक है। एक व्यक्ति जो काम कर सकता है, मेहनत कर सकता है, मजदूरी कर सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है, दूसरी रचनात्मक वृत्ति से कुछ कामकाज करके काम चला सकता है, आजीविका चला सकता है उसकी वृत्ति लाटरी लाटरी करने में चली जायेगी। मुफ्तखोरी की भावना पैदा हो जायेगी। तो जो चीज हम में सुस्त बनने की भावना पैदा करती है, हमको मुफ्तखोरी की तरफ ले जाती है उसको मैं अच्छी नहीं समझता हूं बल्कि बुरी समझता हूं। उस चीज़ की तरफ हमको नहीं जाना चाहिये।

अभी जुए के बारे में कहा गया कि महाभारत काल में भी जुआ था। महाभारत में द्रौपदी तक को जुए में दाव पर लगा दिया था। लेकिन मैं अपनी औरत को जुए पर नहीं लगाऊंगा, हालाकि मैं भी बूढ़ा हो गया, औरत भी बूढ़ी हो गई। "द्यूतं छलयतामस्मि" अगर छल को लीगलाइज करना है तो जुए को भी अपना सकते हैं। लेकिन जुए का समर्थन कोई भी सभ्य समाज का आदमी कभी नहीं कर सकता।

पैसे की जो बात कही गई है कि साहब बहुत पैसा मिल जायेगा। इसमें कोई शक नहीं कि लाटरी से पैसा मिलेगा, तो फिर कमाने घमाने की जरूरत नहीं है। लाटरी खरीदने के लिये बीबी से कह देंगे तुम अपने जेवर बेच दो, लाटरी लेनी है या थोड़ा सा बच्चे के दूध में से बचाकर पैसा निकाल लो। तो इस तरह से लाटरी लेने के लिये पैसा बचाने की प्रवृत्ति पैदा जरूर होगी। लेकिन वह पैसा किस किस के काम आयेगा ? वह पैसा एक आध आदमी को मिल जायेगा। यह पैसा इंसान में जो वृत्ति पैदा करेगा वह वृत्ति, मैं नहीं समझता. कोई अच्छी वृत्ति होगी।

श्री नवाबसिंह चौहान : उदार वृत्ति होगी।

श्री जयनारायण व्यास : उदार वृत्ति नहीं उधार वृत्ति होगी। कोई काम आप ले लीजिये जिससे अनुचित पैसा मिल सकता है। यह हमारा सदन है, इसकी एक प्रतिष्ठा है। अगर बाहर से आने वाले दर्शकों को कह दिया जाय कि भाई इस सदन को देखने के लिये एक रुपया देना होगा और जो विजिटर्स हमारी गैलरियों में आते हैं उनसे कह दिया जाय कि उसका दो रुपया लगेगा, और उनसे यह कहा जाय कि जिस वक्त हमारा सदन नहीं चलता हो तो सभापति की कुर्सी पर बैठने के लिये पांच रुपये देने होंगे तो क्या बुराई की बात होगी ? लेकिन बुराई की बात यह होगी कि यह कुर्सी हमारी भावना का प्रतीक है, यह सदन हमारी भावना का प्रतीक है, वह स्थान भी हमारी भावना का प्रतीक है, और जो बातें हमारी भावना का प्रतीक हैं उनको हम नीलाम पर नहीं लगा सकते--जुए पर नहीं लगा सकते। जो हमारा पैसा है, जो हमारी लक्ष्मी उसको जुए पर लगाना मैं अच्छा नही समझता। यह कहा गया है कि इससे सरकार जो डेवलपमेंट का काम करती है उसमें मदद मिलेगी, अच्छी मदद मिलेगी। सरकार को अगर मदद मिल भी गई तो मैं कहूंगा कि उसमें सिद्धि नहीं होगी। आज भी हमको कुछ बुरे पैसे मिलते हैं। मुझे नहीं पता कहां से मिलते हैं। लेकिन उसका नतीजा क्या होता है कभी कभी

कम्युनिटी डेवलपमेंट के जो आदमी हैं वे जीपों में बैठ कर जाते हैं और सफर करते हैं। कभी कभी लड़कियां अपने काम से जाती हैं तो गलत टी० ए० डी० ए० लिखे देती हैं। जो पैसा अच्छी भावना से आयेगा—अच्छी जगह से आयेगा—उस पैसे के अच्छे परिणाम होंगे। जो पैसा बुरे तरीके से लाया जायेगा उसके बुरे परिणाम निकलेंगे।

श्री नवाबसिंह चौहान : यह भी भाग्य-वाद है।

श्री जयनारायण व्यास : इसमें भाग्य-वादी का प्रश्न नहीं है। प्रश्न तो यह है कि अच्छे का नतीजा अच्छा निकलता है और बुरे का नतीजा बुरा निकलता है। जो पैसा अच्छी भावना से आयेगा उसका अच्छा नतीजा निकलेगा और जो पैसा बुरी भावना से आयेगा उसका बुरा नतीजा निकलेगा। जो पैसा कलुषित भावना से आता है उसका कभी अच्छा परिणाम नहीं होता। यह भी कहा जा सकता है कि वैश्या-वृत्ति को जारी रखने दिया जाय और उस पर सेस लगाया जाय और उसका रुपया डेवलपमेंट के कामों में लगाया जाये। क्या यह बात ठीक है?

श्री शीलभद्र याजी (बिहार) : वैश्या-वृत्ति का लाटरी से मिलान नहीं हो सकता है।

श्री जयनारायण व्यास : मेरा तो यह कहना है कि जो बुरा साधन है वह बुरा है। मैं उन तरीकों को नहीं चाहता हूं जो कि बुरे साधन हैं।

श्री किशोरी राम : इससे तो गवर्नमेंट की आमदनी हो सकती है।

श्री जयनारायण व्यास : गवर्नमेंट की आमदनी बढ़ाने के लिये हम इस तरह की चीजों पर सेस लगायें, यह बात मैं नहीं मान सकता हूं। बुरे तरीके से किसी तरह की आमदनी नहीं होनी चाहिये और न मैं यह समझता हूं कि गवर्नमेंट इस तरह का कोई विचार कर रही है। लेकिन मैं गवर्नमेंट को यह सलाह दूंगा कि बुरी भावना से जो रुपया पैदा किया जाता है उसका बुरा नितीजा निकलता है। अभी मेरे भाई किशोरी राम ने कहा कि दीवाली में जो जुआ होता है उससे लोगों को फायदा होता है। इससे कुछ लोगों को अवश्य फायदा हो जायेगा लेकिन वह चीज तो बुरी है और उसको रोकना चाहिये। इसके साथ ही साथ यह भी कहा जा सकता है कि विदेशों से जब शराब आती है तो क्यों नहीं हमारे देश में देशी-शराब जारी की जाय। मैं समझता हूं कि हमारे देश में जो विदेशी शराब आ रही है उसे रोकना चाहिये और साथ ही साथ देशी शराब पर भी रोक लगाई जानी चाहिये। शराब से जो रुपया प्राप्त होता है उसे भी रोका जाना चाहिय। जो बुरी चीज है और उससे जो रुपया पैदा होता है, उसको प्राप्त करने की कभी कोशिश नहीं की जानी चाहिये। यह अच्छी बात नहीं है, मैं एसा मानता हूं। यह जो लाटरी की वृत्ति है वह :

काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः।
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्।।

वह बैरी हमें लोभी बनने, और काम की वृत्ति में बदल देगी। इस तरह की वृत्ति को हमें छोड़ना चाहिये और इससे लाभ के बजाय पाप ज्यादा होगा।

मेरा प्रस्तावक महोदय से यह कहना है कि अगर सरकार को पैसा देना है तो इस

[श्री जयनारायण व्यास]

तरह की वृत्ति छोड़नी होगी। हमें लोगों से अपील करनी चाहिये, अच्छी भावना से अपील करनी चाहिये कि वे डेवलपमेंट के कार्यों में सरकार को धन दें। हमें धनी लोगों से अपील करनी चाहिये कि वे अपने धन का दस प्रतिशत सरकार को डेवलपमेंट के कार्यों में दे। इसी तरह से हम मेम्बरों से अपील कर सकते हैं कि उन्हें जो एलाउन्स मिलता है उसमें से कुछ पैसा सरकार को दे सकते हैं। इस तरह की बात को मैं समझ सकता हूं लेकिन जो बुरे साधन हैं, जो बुरे तरीके हैं, उनसे हमें पैसा प्राप्त नहीं करना चाहिये। हमें कभी भी बुरे साधन अपनाने नहीं चाहियें और न कभी उनको प्रोत्साहन देना चाहिये।

मेरा खयाल है कि प्रस्तावक महोदय इस प्रस्ताव को वापस ले लेंगे और इस सम्बन्ध में जो बहस सदन में हुई है उससे तो हमें लाभ ही होगा।

लाटरी के सम्बन्ध में करीब करीब सभी बातें कह दी गई हैं। इसमें कोई शक नहीं कि प्राइज बांड्स से लोगों को प्रोत्साहन मिला है। प्राइज बांड्स और नेशनल सेविंग्स के बारे में कुछ विचार किया जा सकता है, लेकिन प्राइज बांड्स की जो मनोवृत्ति है उसमें दायां बायां कुछ फर्क आ जाता है। इस चीज में जो मनोवृत्ति है उसको सामने रखकर हमें प्राइज बांड्स की बात को भी सोचना चाहिये। मैं सरकार से फिर कह सकता हूं कि वह प्राइज बांड्स की स्कीम को वापस ले ले। अगर हम लाटरी की बात को यह मानकर मान लेते हैं कि प्राइज बांड्स की बात मान ली गई है, लाटरी को भी चलने दो, तो इस तरह की वृत्ति अच्छी नहीं है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

SHRI N. M. ANWAR (Madras): Mr. Deputy Chairman, there is a saying in the English language—paradoxical though it may appear, yet I think never was truth uttered much better than that—that the path to hell is paved with the best of intentions, and here we have got a resolution before the House which is a proof in point as to what actually it means for the country—the path to hell is paved with the best of intentions.

Mr. Deputy Chairman, we have been holding our head aloft before the bar of world opinion as a country which has set an example of spiritual values and of moral values, and here at the altar of mammon, if we are to believe the Mover of the Resolution, we have got to prostitute our sense of values. I believe, Mr. Deputy Chairman, it is not by this way that we should encourage things which we want to develop for the good of our country. No doubt we have got to appreciate the motives that have prompted the Mover of this Resolution that he wants every avenue to be exploited in order that we can augment the Plan, in order that we can also accelerate the implementation of the health and other social service schemes envisaged in the Plan. But as a country which has produced Mahatma Gandhi who has held aloft that it is the means that count and not the end, I believe this is not the way in which we are going to honour his memory. On the contrary if there is one whose soul should now feel very happy that he has got devotees even in this country of great spiritual values, it is Machiavelli because it was he who said: "It is not the means that count, and no matter what the means are, so long as we have the end in view let us try to pursue it by means fair or foul." I believe, Mr. Deputy Chairman, here is a measure by which, if only the Government should adopt it, we may go down before the bar of world opinion that we as a country, as a nation, as a party, have no right to vindicate the principles for which Mahatma Gandhi had stood and fought the battle of our freedom. He said that it was the means that counted and he set a premium upon truth. Believe

me, Mr. Deputy Chairman, I have myself witnessed as to what takes place at Derby. I was, of course, there many a time in that country where they do not have this high sense of values. They take it as a national holiday and go about it as a pastime, in fact every man, woman and child would like to devote a little money in order that they could take part in this pastime. But that is not what is actually suggested here. That can well be rather in keeping with the genius of that soil, but here we have been born unto traditions, unto a heritage which always set spiritual values high, and definitely, therefore, to say that we have got to take our inspiration from ever so many countries overseas is not the way of approach to this problem. On the contrary we have to give a lead and an example and serve as an inspiration for ever so many countries overseas that in spite of our difficulties, that in spite of the odds, that are against us in the implementation of the Plan, we have been trying to pursue the path of good means and to see that we hold our spiritual values high.

Reference has been made to ever so many examples of gambling in this country. But even there, Mr. Deputy Chairman, that should not be an argument that we should have to expand this area of gamble. I know that gambling is rooted in the spirit of man, but if this State wants the moral sanctions of society, it must have to curb that spirit and not that it should set a premium upon that spirit. As many of us, Members of this House, should themselves have experienced in their life that people who go to the racecourse display the psycho-pathology of our social life. They go there with plenty of hopes and ambitions, and like Alnascher they dream whom even opium-eaters should envy, but by the evening when the race is over and when they return, particularly the poor gentry, we know how they have been victimised by this gambling, how they have become poorer for the day.

Therefore, even granting that we have committed a mistake in allowing horse-racing, a tradition which we have inherited from the British regime, let us make it clear that, in going in for a noble cause, we shall not allow this spirit of gambling any more to extend. I know that the Mover of this Resolution is fully alive to the problems of social service but my real feeling is that he will, on second thoughts after hearing the proceedings of this House, himself come forward to withdraw this Resolution because I do not want that it should go against his fair name, that he did not value very much the means. Let us make this clear.

Mr. Deputy Chairman, one of the arguments that he has advanced is that every man wants to grow rich, richer and still richer, and grow rich as quickly as he can. I know that this is an experience which we come across in our everyday life. But I must only say this. I wish to contradict my friend's "easy-come-easy-go" approach. In order that we should have to grow rich quickly, I think that this is not the means that we will have to suggest to our country. We have come here as representatives of the people and we have to set an example as to how best they have to conduct themselves in their way of life. We have to tell them in the language of the people. In fact, I was really surprised that one or two Members were even quoting chapter and verse from the scriptures. I was wondering; they knew not what they spoke. On the contrary, all scriptures make it clear that man does not live by bread alone. Is it for that bread that we have to sell our soul? Is it that we will have to go before the bar of world opinion that we do not care what the means should be. Well, I feel that we should not allow this Resolution to be adopted and I would make this appeal to the House. Even though he might have been prompted to bring forward this Resolution with the very best of considerations for the good of our country, on second thoughts, after

[Shri N. M. Anwar.]

listening to the arguments that have been advanced on the floor of this House, I am sure he will himself come forward to withdraw this Resolution. In many States, and particularly in the State which I have the honour to represent, we have been implementing the scheme of prohibition. It definitely costs a tremendous lot to the revenues of the State but yet we have been pursuing it vigorously. We know that there has been some illicit distillation going on; we know also that the rules sometimes are more honoured in their breach than in their observance. But that is only an infinitesimal percentage of the problem. It is quite possible that the people in the villages are not fully educated, are still not fully alive to the good which the State has got in mind for them. But why is it that the Government, particularly the State from which I come, have committed themselves to the policy of prohibition? I am sure that there are many other States in our country where too this policy of prohibition has been implemented vigorously. That is because we do not want money from the tainted source for the national exchequer. An argument has been advanced here that particularly in these days when we are struggling for foreign exchange, here is one more opportunity that we will have to exploit and see that we augment our revenues for the national exchequer. But believe me, Mr. Deputy Chairman, the arguments that have been advanced in that direction themselves defeat their purpose. Most of the transactions that have been carried on have gone on without the knowledge and without the sanction of the powers that be. And if tickets are being sold in this country—a foreign sweep-stake sometimes declares dividends—for the nationals of the country, I wonder how such money could at all be permitted to go out and how the proceeds of that sweep-stake could be distributed in this country when these subscriptions have gone out of the country without the knowledge of the authorities. I am sure the hon. Minister will take cognizance of this information, because I can little believe how foreign exchange can go out of this country. I was amazed, in fact amused for a while, how money by millions of rupees had been going out of our country by way of investment in these sweep-stakes. I know that there are sweep-stakes in almost every country of Europe. I have had the privilege of visiting many countries and hearing quite a lot about these sweep-stakes. But how such contraband has been going on so merrily for so long is a matter for investigation, and I am sure the Government will pursue it and see that the culprits are brought to book, because we shall not allow that. There shall be nothing of the kind in our own country by which such precious money as we need should be allowed to go out of our country. There are very many weighty and lofty considerations as to why foreign exchange is not so readily made available to us. People go in for higher studies; people go on missions—in fact, I myself intend leaving for West Germany tomorrow. But I know how we have to confront ourselves with the problem of finding foreign exchange. We have got to give lofty arguments to justify why we need this or that modest sum. The authorities are so strict; they implement the rules and regulations very severely. I congratulate them; they do it because it is in the larger interests of the national exchequer. But here I have got information which is to me very much confounding, how millions and millions of rupees of our country are being invested in these sweep-stakes in different parts of the world and how sometimes even dividends, the prize moneys, are being allowed to enter this country without the knowledge of the authorities. That is something which I cannot understand.

One more argument was advanced in the course of the debate—and by a very senior Member of this House—that we would have to see how best

we could attract black money through the medium of Prize Bonds and things like that. Believe me, Sir, whatever can be said behind the scenes or off the record, let it not be said on the floor of this House that we have got to attract black money because the State should not take cognizance of that money even if the facts are—and that is the hard reality of the situation—that there is so much of black money underground. The governmental machinery will have to see that it keeps its hands off from all such tainted sources and that is why I feel very strongly on this not only on a moral plane but in the very interests of the scheme that the Government have in mind and that the hon. Mover of the Resolution has got in mind. Let us see that our hands are clean, our conscience is clear and that we stand before the bar of world opinion as worthy of the heritage of Mahatma Gandhi, the architect of our freedom.

DR. W. S. BARLINGAY (Bombay): May I move an amendment to this Resolution, Sir? I want to move that the entire Government should be run on the basis of lotteries.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Order, order.

श्री शीलभद्र याजी : माननीय डिप्टी चेयरमैन महोदय, अभी जो प्रस्ताव हाउस के समक्ष साथी कुर्रे जी ने पेश किया है उसका मैं सहर्ष समर्थन करता हूं। अभी रिजोल्यूशन की मुखालिफत में नैतिकता, सत्य, अहिंसा और गांधी जी से लेकर गीता और महाभारत तक पर लेक्चर हुआ। हम राजनीतिज्ञ हैं, एक पालिटिशियन हैं और पालिटिशियन होने के नाते हमें यह देखना है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये-जिसमें कि इतना अधिक रुपया हमें इकट्ठा करना है और खर्च करना है—वह रुपया हमको कहां से मिलेगा। तो इसमें सत्य, अहिंसा और नैतिकता पर लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं थी। हमारे भार्गव जी ने इसकी मुखालिफत करते हुए यह भी कहा कि यह जीवन ही एक गैंबलिंग है, यह जीवन ही एक जुआ है। हमारे पणिक्कर जी ने एक बार कहा था कि हमारे जितने एम्बेसेडर हैं, हमारे जितने मंत्री हैं, वे चतुर राजनीतिज्ञ हैं। तो जो श्रीकृष्ण के और चाणक्य के मानने वाले हैं उनके लिये गांधी जी की उपमा देने की जरूरत नहीं थी। गांधी जी ने सन् १९२१ में अहमदाबाद में कहा था कि कांग्रेस का उसूल सत्य और अहिंसा होना चाहिये लेकिन कांग्रेस कमेटी ने उसको ठुकरा दिया और गांधी जी को रोना पड़ा। जब लड़ाई होती थी तो लड़ाई के लिये गांधी जी को डिक्टेटर बनाया जाता था और वह सत्य और अहिंसा के जरिये से संघर्ष चलाते थे लेकिन कांग्रेस ने अपने अकीदा में सत्य और अहिंसा को लाने से इंकार किया क्योंकि यह एक राजनैतिक पार्टी है। यदि हम उसको मानते तो आज काश्मीर के बार्डर पर चर्खे की या तकुली की बैटेलियन जाती और हमारी यह फौज नहीं जाती और देश की क्या हालत होती, यह आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं।

इस प्रस्ताव में कहा गया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये, स्वास्थ्य के लिये, सामाजिक सेवा के लिये किस तरह से रुपया इकट्ठा किया जाय। जब हम दूसरे जरियों से इसके लिये पैसा लेते हैं तो क्या हम जुआ नहीं खेल रहे हैं? इसमें जुएँ की कोई भावना नहीं है। इसमें यह है कि अगर जनता इसमें पैसा दे तो हमें पैसा इकट्ठा करना है। जिस तरह से कि हमारे हाउस में जब सिनेमा की बात आती है तो सब इसकी मुखालिफत करते हैं लेकिन नागपुर कांग्रेस में हमने जरा सा कह दिया कि मधुबाला आ रही हैं, अशोक कुमार आ रहे हैं, जानी वाकर आ रहा है तो १ करोड़ की जगह १ करोड़ ३४ लाख रुपया लघु-बचत आन्दोलन के लिये मिल गया। तो एक चतुर राजनीतिज्ञ होने के नाते हमको यह देखना है कि यदि इसके जरिये से तृतीय

[श्री शीलभद्र याजी]
पंचवर्षीय योजना के लिये हम ज्यादा से ज्यादा रुपया इकट्ठा कर सकते हैं तो इस पर हमें एक राजनीतिज्ञ की हैसियत से सोचना चाहिये न कि एक धार्मिक उपदेशक की तरह से और इस पर नैतिकता के ऊपर लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है।

माननीय डिप्टी चेयरमैन महोदय, इसी लाल किले में हमारा एक बार कोर्ट-मार्शल हो रहा था तो आकिनलेक साहब ने हमसे कहा कि आप बहुत झूठ बोलते हैं। तो हमने कहा कि क्या झूठ बोलते है। इस पर उन्होंने कहा कि गांधी जी ने कहा है कि सब प्लान खोल देना चाहिये लेकिन आप कुछ बोलते ही नहीं हैं। तो हमने कहा कि क्या आप राजनीति की परिभाषा जानते हैं ? वह क्या है ? Politics! Thy name in intrigue and insincerity. And politics has been compared to prostitutes. This is modern politics. हमने कहा कि आप आज हिन्दुस्तान के कमांडर-इन-चीफ हैं, आप एक लफंगे और झूठे हैं और आप ही नहीं बल्कि जितने भी राजनीतिज्ञ है वे अपने देश की हिफाजत के लिये ऐसे हैं, नहीं तो आप या वे कमांडर और मंत्री का पार्ट अदा नहीं कर सकते। यदि आप अपनी सेना को पश्चिम की तरफ भेजते हैं तो क्या यह नहीं कहते हैं कि पूर्व की तरफ हमारी सेना जा रही है ? तो हमें राजनीतिज्ञ की हैसियत से इस पर सोचना चाहिये, हम राज्य सभा के सदस्य हैं, हम चतुर राजनीतिज्ञ हैं और दुनिया को राजनीति सिखाने वाले हैं, हम नैतिकता पर लेक्चर न दें। नहीं तो आपको साधु संत महात्मा लोगों की जमात में बैठना चाहिये और यहां नहीं बैठना चाहिये। जब, हम लोगों को शराब पिला कर पैसा इकट्ठा करते हैं, हालांकि हमारी प्राहिबिशन की पालिसी है, और गरीब किसानों से भी पैसा लेते हैं तो फिर इसमें क्या खास बात है ? जब जब न्यू टैक्सेज़ का मेजर पेश हुआ मैंने एक समाजवादी होने के नाते उसका समर्थन किया क्योंकि देश की तरक्की के लिये उनकी जरूरत है। आपने देखा कि सिनेमा स्टार का नाम मुंह पर लाने से लघु-बचत आन्दोलन में हम सफल होते हैं तो फिर इन सब बातों में क्या लॉजिक हो सकता है ? जब हम इस तरीके से राष्ट्रीय पैमाने पर आयोजना कर रहे हैं तब शुद्ध नैतिकता पर भाषण देने की ज़रूरत नहो है। मै सोचता हूं कि यदि सरकारी पैमाने पर हिन्दुस्तान के कोने कोने में यह चीज़ हो सके तो कितना अधिक पैसा इकट्ठा हो सकता है Many a little makes a mickle. बूंद बूंद कर के तालाब भरता है।

इसमें एक सवाल यह भी है कि जब लोगों को यह मालूम होगा कि हमको एक गाड़ी मिल जायगी, या एक साइकिल मिल जायगी या और कोई चीज़ मिल जायगी तो गांव में सब लोग कुछ न कछ बचा कर के इसमें रुपया जमा करेंगे और सरकार को इससे बहुत फायदा होगा। इसलिये मै समझता हूं कि यह एक बहुत मौज़ूं प्रस्ताव है, यह एक उचित प्रस्ताव है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमको बहुत पैसा लगाना है और इसका अभी तक कोई हिसाब नहीं लग पा रहा है कि वह पैसा कहां से आयेगा। उसके लिये लोगों पर टैक्स भी लगाना होगा और उसके लिये लोगों को मजबूर करना होगा लेकिन इसमें यह चीज़ है कि वे स्वेच्छापूर्वक इसमें पैसा दें। इसमें यह चीज़ कहां ला रहे हैं कि लोगों को लाटरी लेने के लिये मजबूर करेंगे ? इसमें यह है कि स्वेच्छापूर्वक—विलिंगली—लोग लाटरी में पैसा लगायेंगे तो पैसा आयेगा और उस पैसे से अस्पतालों के लिये, समाज-सेवा के काम के लिये, प्लानिंग के जो काम हैं उनके लिये, हम ज्यादा से ज्यादा रुपया दे सकेंगे। जब हम दूसरे देशों से कर्ज लेते हैं और दूसरे तरीकों से पैसा इकट्ठा करते है तब हम

समझते हैं कि इसमें हमको नाक-भौं सिकोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और हमारे जितने माननीय सदस्यों ने इस पर नैतिकता के ऊपर सत्य और अहिंसा के ऊपर भाषण दिया है उसकी ज़रूरत नहीं है ।

योजना का काम आपको चलाना है और उसके लिये पैसा लगाना है लेकिन वह पैसा हम कहां से लायेंगे ? कर का मिलना मुश्किल है और कितने दिनों तक हम दूसरे देशों से कर्जा लेंगे, तो जितने रिसोर्सेज देश के अन्दर हैं उनसे ही काम चलाना है और इसमें यह चीज़ बहुत कारगर होगी । तमाम जनता में, गरीब से ले कर अमीर तक में यह प्रलोभन होता है कि लाटरी के जरिये से एक चीज़ मिल रही है तो उसको ले लो । तो पैसा इकट्ठा करने के लिये लाटरी की व्यवस्था उचित है । इसका जो विरोध कर रहे थे उन्होंने कहा कि जीवन ही एक गैंबलिंग है, जीवन ही एक जुआ है । तो राजनीति भी, एक जुआ है और उसके, लिये जुआ जुआ बोलने की ज़रूरत नहीं है । देखना यह है कि पैसा कहां से आ सकता है । कर के रूप में उसे लें या स्वेच्छापूर्वक जनता से लें, यह हमें देखना है । मैं समझता हूं कि यदि ज्यादा से ज्यादा लाटरी की व्यवस्था की जाय तो ज्यादा से ज्यादा पैसा स्वेच्छापूर्वक, विलिंगली, आ सकेगा । हमारे जो राजनैतिक कार्यकर्त्ता हैं, चाहे वे किसी पार्टी के हों, वे यदि तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये इसमें थोड़ा हाथ लगायें और सब लोगों को इसके लिये एनकरेज करें कि सरकार की जो लाटरी की व्यवस्था है उसमें ज्यादा पैसा लगाना चाहिये तो मैं समझता हूं कि बहुत पैसा आ सकता है । यह जो स्कीम है, उचित स्कीम है ।

हमारे कुछ माननीय सदस्य हमारे मंत्री महोदय को भड़का देते हैं और मुझे आशंका है कि वे भी शायद महात्मा गांधी को ले कर के शुरू करेंगे और देश की नैतिकता की बात को ला कर के हमें जवाब देंगे लेकिन उनसे मेरा कहना है कि हम राजनीतिज्ञ हैं और एक चतुर राजनीतिज्ञ और डिप्लोमेट होने के नाते हमें चीजों की असलियत को देखना है कि किस तरीके से पैसा इकट्ठा हो सकता है । चूंकि इस तरह से ज्यादा पैसा इकट्ठा होने की आशा है, इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इसका समर्थन ही नहीं करता बल्कि जिन लोगों ने इसकी मुखालिफत की है उनसे, आपसे और सरकार से और मंत्री जी से अपील करता हूं कि इस पर ठंडे दिल से सोचने की ज़रूरत है । उन्हें नैतिकता का पाठ नहीं सिखलाना चाहिये बल्कि इसे सहर्ष कबूल करना चाहिये क्योंकि लाटरी की व्यवस्था करके हम करोड़ों रुपया इकट्ठा कर सकते हैं । अभी इसको अगर नहीं भी कबूल करते हैं तो आगे चल कर इसे कबूल करना ही पड़ेगा, क्योंकि और तरीके से काम चलने वाला नहीं है । जब हम टैक्सेशन को बढ़ाते हैं तो प्रदर्शन होते हैं, डिमांस्ट्रेशंस होते हैं । इसलिये स्वेच्छापूर्वक लाटरी से पैसा लेना ज़रूरी है । इस चीज़ को मंत्री महोदय क्यों नहीं कबूल करेंगे, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है । हमारे श्रीकृष्ण भगवान् एक चतुर राजनीतिज्ञ थे, जिस तरह से गांधी जी की उपमा दी गई, उसी तरह से मैं श्रीकृष्ण भगवान् की उपमा देता हूं । उन्होंने कहा कि दुर्योधन की जांघ में मारो, नीचे मारो, यह कहा कि अश्वत्थामा मर गया और बीच में शंख बजा दिया । तो इस तरह का चतुर राजनीतिज्ञ होना है । किसी ने मोरेलिटी पर भाषण दे दिया, नैतिकता पर भाषण दे दिया, सत्य और अहिंसा पर भाषण दे दिया तो इससे देश का शासन भी ठीक से नहीं चलेगा और आप एक चतुर शासक भी नहीं हो सकते हैं । इसलिये यदि आप जनता पर टैक्स लगाने से जो प्रदर्शन और डिमांस्ट्रेशन होता है उसको रोकना चाहते हैं तो फिर स्वेच्छापूर्वक लाटरी के द्वारा रुपया लेने की कोई व्यवस्था होनी चाहिये

[श्री शीलभद्र याजी]

और इस प्रस्ताव को सहर्ष सरकार को मंजूर करना चाहिये। इन शब्दों के साथ साथी कुरें जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं।

SHRI SONUSING DHANSING PATIL (Bombay): Mr. Deputy Chairman, Sir, I am an uncompromising opponent to this ugly Resolution, and I have got solid reasons to say so.

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE: Are we not politicians?

SHRI SONUSING DHANSING PATIL: I am a politician, and I claim to be a better politician than Mr. Yajee who changes his politics whenever it suits him. It is rather very surprising and paradoxical that Mr. Yajee gave the impression that morality is a sort of taboo to a clever politician. Those who are trained in the Gandhian way should try to keep even politics as pure as possible, to the extent humanly possible, knowing as we do the limitations and qualifications of a party which can govern the country in a fair and square manner. The question is whether by putting certain words in this Resolution, namely that Government should organise National Lotteries to raise money for implementing the health and other social service schemes envisaged in the Plan, it gives the right solution to the raising of funds, whether the approach suggested for the purpose is right—even though the word "National" may be very attractive.

But the question is whether the Government should organise this business on a national scale and get money for the purposes which apparently appear to be very laudable and attractive. The question is whether we as a Government should try to improve the moral fibre of the society or should try to encourage loteries which involves an element of uncertainty. Instances have been quoted that Government indirectly introduced an element of lottery by accepting or introducing the Prize Bonds. But, Sir, if we look to the scheme of Prize Bonds, it is not a sort of lottery. It only asks to make certain sacrifices for a particular period.

SHRI AKBAR ALI KHAN (Andhra Pradesh): That is the interpretation.

SHRI SONUSING DHANSING PATIL: That is very clear. It is not an interpretation. Up to five years you are asked to wait because your money is not lost. But here the money is lost. A number of people indulge in this vice under the delusion that they are likely to get some sort of . . .

DR. W. S. BARLINGAY: This is the distinction between tweedledum and tweedledee.

SHRI SONUSING DHANSING PATIL: It may be. After all, I have made it clear that the Government cannot avoid certain things which are, as far as possible, within the fair limit of morality. It is not a sort of taboo if they can do certain things through bettter education. But to compare Prize Bonds to the national organisation of lottery is something which appears to be rather ridiculous. Howsoever clever politicians may try to convince that the Government is meant for the material benefit of the people and as such should not try to unnecessarily indulge in ideas of morality and religion and so on and so forth, after all this moral fibre is the very fibre which has given sustenance to India from times immemorial. If this sort of a national lottery is organised, it would mean that Government will have to take special pains to make the necessary propaganda and bring about the necessary organisation which will float this lottery and collect money which would be utilised for the laudable purpose of health and social service schemes envisaged in the Plan. Sir, I would better drop all the social service schemes and health plans in the Third Plan if we are not able to get the necessary money through our

internal resources or through loans from abroad, or through grants or hard work rather than like the country to go in for this kind of national lotteries and create an atmosphere in the country which would spoil our moral fibre.

Sir, let us not go to the extent of saying that means are convertible with ends. But, after all, our means should be as fair as the end. Several friends who opposed the resolution cited instances and expressed surprise at our committing lapses. When we are faced with a difficult situation, can we not appeal to the country to put in more hard labour, accept less wages and build up the nation which will stand erect in the face of difficulties

Sir, objection is taken to horse racing as it involves an element of lottery. But it has a bright side also which we have to consider. There is the question of building up the pedigree of good horses in the country. Besides, there is an element of amusement and recreation in horse racing. But what is the recreation in the lottery except that it is likely to bring by chance a big amount which may or may not come off? As I pointed out earlier, the element of uncertainty involved in the lottery is not going to put us on a straight basis but will involve a large majority of people into losses without bringing them any good.

The other side to this question is that in the country there are already a number of evil practices going on. There is already a very powerful section of the so-called enlightened public opinion which stands for the scrapping of prohibition. Very surprisingly enough, one Mr. R. P. Masani, while presiding over the Hotel Keepers' meeting, said that after the bifurcation of Bombay, the Bombay Government will retrace its steps and scrap prohibition. A reply has already come today from the hon. Minister, Shri Adani, saying that they are not going to do anything of that sort. This section of opinion does not see any harm in scrapping prohibition and getting a substantial amount of money. As far as I know, the Bombay State is now losing about Rs. 20 to Rs. 21 crores annually on account of prohibition. They say that this money could be utilised for better schemes like social service schemes in the Plan. The answer is very clear. We are committed to a certain policy whereunder we are not going to use this tainted money and create an atmosphere in the masses which will make them lose very substantially in the long run. In the beginning they may enjoy but afterwards become paupers.

Therefore, if the Government takes the initiative in this field by openly allowing the people in this glorious game of national lotteries, it will not be doing its duty. I think the Government has got the very responsible duty of educating the ignorant and very poor masses and to raise their standard both materially and morally. On the other hand, if they indulge in this thing, I am afraid the future of this country is very dismal.

Sir, an argument is advanced that while we are too short of money we must anyhow raise the money to deliver the goods to the people. In the light of this argument this particular resolution may appear very tempting and persuasive. One in apt to make a suggestion or even apt to accept it but the spirit and the far-reaching effects that are involved in this resolution are certainly going to be detrimental to the interests of the nation so much so that people will openly say that if the Government came to their help they would freely indulge in this, what you call, fundamental right.

Sir, it is said that a man has got three or four fundamental rights. Gambling is one of them. Drinking and prostitution are, perhaps, another two such rights. But whether we should allow these fundamental vices to have their sway and whether the Government should be a party to it, is a matter for all the thinkers and teachers. I for one—though I may not call myself a very true Gandhiite —have immense faith in the principle

[Shri Sonusing Dhansing Patil.]

that our means should be as fair as our ends. Howsoever, the clever politician may try to build up the nation in his own way and howsoever he may try to ignore the moral fibre which is the pressing need of the hour, I still feel that we must stand fast to our principles. Then alone we can build up the nation. By dint of our labour and by fairer means alone we can build up a nation.

With these remarks I totally oppose the resolution.

ANNOUNCEMENT *RE* GOVERNMENT BUSINESS FOR THE WEEK COMMENCING 11TH APRIL, 1960

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SATYA NARAYAN SINHA): Sir, with your permission, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing 11th April, 1960, will consist of:—

(1) Further consideration and passing of the Supreme Court (Number of Judges) Amendment Bill, 1960.

(2) Consideration and passing of the Indian Boilers (Amendment) Bill, 1960.

(3) Consideration of a motion for reference of the Delhi Primary Education Bill, 1960, to a Joint Committee.

(4) Discussion on the Third Annual Report of the University Grants Commission on a motion to be moved by the Minister of Education.

(5) Further consideration of the Dowry Prohibition Bill, 1959.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 2.30 P.M.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at half past two of the clock, THE VICE-CHAIRMAN (PANDIT S. S. N. TANKHA) in the Chair.

RESOLUTION *RE* NATIONAL LOTTERIES FOR RAISING FINANCE FOR SOCIAL SERVICE SCHEMES—*continued.*

SHRI AKBAR ALI KHAN: Mr. Vice-Chairman, the debate on this Resolution has taken a somewhat peculiar turn. So far as the ideological and the moral points of view are concerned, I do not think there will be anybody in this House who will conciously support a measure which will lead to things which do not go to build up our moral stature. But the position that I see here is this, or rather the spirit of the Resolution is this. When there is a certain evil existing, are we to leave it as it is? Or should we try to bring it under control? That is the issue before us now. If an impression has been created by some speeches that we are now introducing a measure which will encourage lotteries and other such things, things that pertain to lotteries, then I respectfully submit that I do not accept that interpretation. If somebody says, "No introduce it with all force and have a measure to carry on lotteries", I do not agree with that. After reading this Resolution what I understand or the conclusion to which I arrive is that there exists an evil. There is no place, no village, no city where this spirit is not going on in full force. I have had occasion to go to horse-races.

DR. R. B. GOUR: In what capacity, did my hon. friend go there, may I know?

SHRI AKBAR ALI KHAN: Not in that capacity which my hon. friend occupies and which I have not had the privilege to occupy. My point is this. Of course, I have seen them going, in large numbers to Ooty, Bangalore, Calcutta in high spirits, but when they come back, 99 per cent. of them are in very deplorable condition so far as their pockets and their mental conditions are concern-